

राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन और रूस साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की और यूक्रेन व रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक-दूसरे से बातचीत की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मोदी ने कहा कि भारत, शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी ने चर्चा के दौरान एक ऐसा अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच 'व्यावहारिक बातचीत' की आवश्यकता जताई जो व्यापक स्वीकार्यता बनाने में मदद करे और क्षेत्र में शांति व स्थिरता में योगदान दे सके।

वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठना चाहिए और उन्हें इस संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने होंगे। आज मैं यूक्रेन की धरती पर आपके साथ शांति और आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत, शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान दे सकता हूँ तो मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग भी जानते हैं कि भारत का शांति प्रयासों में सक्रिय योगदान रहा है और उसका दृष्टिकोण लोगों पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह भारत की प्रतिबद्धता



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले।

भारत और यूक्रेन के बीच चार समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन ने शुक्रवार को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित होगा।

आज इतिहास रचा गया। यूक्रेन की आजादी के बाद से हमारे स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है। इस यात्रा के बाद हम रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निरंतर सैन्य-तकनीकी सहयोग के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर भी सहमत हुए।

-वोलोदिमीर जेलेंस्की, राष्ट्रपति यूक्रेन

कतर में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जप्त करने का मुद्दा उठाया भारत ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जप्त किए जाने का मुद्दा कतर के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पवित्र ग्रंथ के एक स्वरूप को कतर के अधिकारियों ने वापस कर दिया है और यह आश्वासन दिया है कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा।

विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मुद्दे के शीघ्र समाधान की आशा करते हैं और इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रवक्ता

रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कतर के अधिकारियों द्वारा जप्त किए गए गुरु ग्रंथ साहिब की खबरें देखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कतर के समक्ष पहले ही इस मामले को उठाया है और दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने वहां सिख समुदाय को घटनाक्रम से अवगत कराया है। इस मुद्दे पर जायसवाल ने कहा, 'कतर के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों/समूहों से गुरु ग्रंथ साहिब के दो स्वरूप जप्त किए थे, जिन पर कतर की मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने का आरोप लगाया गया था।'

उन्होंने कहा कि दूतावास ने स्थानीय कानूनों और नियमों के दायरे में हरसंभव सहायता प्रदान की है। पवित्र ग्रंथ के एक स्वरूप को कतर के अधिकारियों ने वापस कर दिया और यह आश्वासन दिया गया कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा।

नेपाल में भारत की बस नदी में गिरी, 27 की मौत महाराष्ट्र के ये यात्री 104 तीर्थयात्रियों के समूह का हिस्सा थे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

मध्य नेपाल में एक भारतीय पर्यटक बस शुक्रवार को राजमार्ग से पलटकर 150 मीटर नीचे तेज बहाव वाली मर्यागदी नदी में गिर गई, जिससे कम के कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। बताया गया कि 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की यह बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी यह तनहुँ जिले के आड़ना पहारा में राजमार्ग से पलट गई। बस में चालक और सह-चालक समेत 43 लोग सवार थे। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के उप प्रवक्ता शैलेंद्र



नेपाल में नदी में गिरी बस।

थापा ने बताया कि 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 16 लोग घायल हुए हैं,

महिला व चार बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, दो गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई में एक महिला और उसके चार नाबालिग बच्चों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर के क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 30 वर्ष के आसपास है। दोनों को मुंबई से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। वे कुशीनगर में महिला के पड़ोसी थे और पिछले कुछ वर्षों से मुंबई

मुंबई से पकड़े गए आरोपियों की पहचान अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी के रूप में हुई है। आरोपी युपी के कुशीनगर में महिला के पड़ोसी थे और पिछले कुछ वर्षों से मुंबई में छोटे-मोटे काम कर रहे थे।

में रहकर छोटा-मोटा काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी को कुशीनगर की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें

अध्ययन

दिल्ली : चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबकर किशोर की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बारिश के पानी में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेकानंद कैप निवासी 15 वर्षीय सौरभ के तौर पर हुई है। घटना के वक्त वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश के पानी में खेल रहा था। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और एक वाहन के नीचे फंस गया।

पुलिस के मुताबिक, चाणक्यपुरी के सेंट मार्टिन रोड स्थित ब्रिटिश स्कूल के पास शुक्रवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर जलभराव हो गया था।

बेबाक बोल

इति गारंटी

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष ने जनता को जिस शब्द से सबसे ज्यादा डराया, वह था गठबंधन। गठबंधन यानी कमजोर सरकार, जिसके फैसलों की कोई 'गारंटी' न हो।

पेज 7

शराब घोटाला : सीबीआइ ने कोर्ट को बताया केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के मुकदमे की मंजूरी मिली

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी। वहीं, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। जमानत याचिका और सीबीआइ द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

दिल्ली की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में सीबीआइ ने बताया कि कथित शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी को अब दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की आवश्यकता मंजूर मिल गई है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआइ को इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने को 15 दिन का समय दिया था।

दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका और सीबीआइ द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के

रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से चार लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 23 अगस्त।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार देर रात हुए भूस्खलन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। ये सभी नेपाल के श्रमिक थे। एक अन्य घटना में हरिद्वार जिले के कांगड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गया। इसके अलावा बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह-जगह हुए भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले फाटा गांव में गुरुवार देर रात करीब 1:20 बजे हेलीपैड के पास भूस्खलन हुआ।

-पूरी खबर पेज १५

दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी, सीबीआइ ने कोर्ट में दी जानकारी। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआइ को इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने को 15 दिन का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई पांच सितंबर तक टली।

लिए दो दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआइ ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और इसे बीते गुरुवार रात आठ बजे उन्हें सौंपा गया। केजरीवाल ने उन्हें जमानत से इनकार किए जाने और सीबीआइ द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। इस पर सीबीआइ ने शीर्ष अदालत में विस्तृत हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल को 25 जून को उनसे पूछताछ करने के बाद ही गिरफ्तार किया था।

सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) लेने से भी पांच साल के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा 24 इकाइयों पर

21 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उसपर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अनिल अंबानी नीत रिलायंस समूह की कंपनी को इस संबंध में भेजे ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के धन की कथित हेरा-फेरी की कई शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने किसी भी नियामकीय उल्लंघन का पता लगाने के

बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

एक नए अध्ययन के अनुसार सड़कों पर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वास्तविकता में प्रयोगशाला परीक्षणों से कहीं अधिक है और सीएनजी वाहन उच्च स्तर पर नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के प्राधिकारियों के सहयोग से 'रियल वर्ल्ड एमिशन (टीआरयूई)' पहल के तहत किए गए इस अध्ययन में सड़कों पर चलने वाले वाहनों के उत्सर्जन को मापने के लिए 'रिमोट सेंसिंग' तकनीक का उपयोग किया गया।

वैश्विक 'थिंक टैंक' इंटरनेशनल कार्सिल आन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) के तकनीकी विशेषण के साथ किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत चरण-छह (बीएस-6) वाली निजी कारों से नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जन भारत चरण-चार (बीएस-4) कारों की तुलना में 81 फीसद

कम है। इसी तरह बीएस-4 बसों की तुलना में बीएस-6 बसों से 95 फीसद कम नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन होता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सीएनजी से चलने वाले वाहनों से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए हल्के माल वाहन अपनी प्रयोगशाला सीमा से 14.2 गुना तक नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जबकि टैक्सियां चार गुना अधिक मात्रा में उत्सर्जित करती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, सड़क पर वाहनों से होने वाले वास्तविक उत्सर्जन पर ध्यान देना जरूरी है, न कि केवल उनके प्रयोगशाला परिणामों पर।

टैक्सी और हल्के माल वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहन निजी कारों की तुलना में बहुत अधिक नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित करते हैं, भले ही वे उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हों। 'आइसीसीटी इंडिया' के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि परिवहन वाहनों से होने वाला वास्तविक उत्सर्जन प्रयोगशाला परीक्षणों में बताए गए आंकड़ों से काफी भिन्न होता है। भारत में पहली बार हमने सड़कों पर मोटर वाहनों से उत्सर्जन के पर्याप्त आंकड़े एकत्र किए हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी उत्सर्जन परीक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करें तथा शून्य-उत्सर्जन वाहनों को अपनाने के प्रयास करें। एफआईए (फेडरेशन इंटरनेशनल डी लह्वआटोमोबाइल) फाउंडेशन की उप निदेशक शोला वाटसन ने कहा कि अध्ययन ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएनजी वह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन नहीं है जिसका वादा किया गया था जबकि दिल्ली प्रदूषण से जुड़ा रही है, जो शहर के लोगों के दम घोट रहा है। अध्ययन ने दिखाया है कि यह कम दिखाई देने वाला घातक



लह्वआटोमोबाइल) फाउंडेशन की उप निदेशक शोला वाटसन ने कहा कि अध्ययन ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएनजी वह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन नहीं है जिसका वादा किया गया था जबकि दिल्ली प्रदूषण से जुड़ा रही है, जो शहर के लोगों के दम घोट रहा है। अध्ययन ने दिखाया है कि यह कम दिखाई देने वाला घातक

खबर कोना

शख्स को ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 अगस्त।

थाना दादरी क्षेत्र के पैरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक रोक कर टायर जांच रहे शख्स को पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट ढाई सप्ताह बाद थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है। पुलिस ने बताया कि जनपद अलीगढ़ निवासी कृष्ण वीर ट्रक पर सहायक (परिचालक) के रूप में नौकरी करते थे। वह गत 5 अगस्त को ट्रक चालक रakesh के साथ पंजाब से कानपुर के लिए जा रहे थे। जब वह पैरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दनकौर टोल से करीब 800 मीटर पीछे थे, तब कृष्णवीर ट्रक को रोककर टायर की जांच करने लगा। इसी बीच पीछे से आ रहे टाटा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। दिल्ली के ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान 11 अगस्त को उनकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है।

कार शोरूम पर भारतीय किसान परिषद का धरना

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 अगस्त।

थाना दादरी क्षेत्र के जीटी रोड स्थित एक कार शोरूम पर भारतीय किसान परिषद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आरोप है कि शोरूम से कार खरीदने के बाद कुछ किलोमीटर चलने पर ही अचानक खराब हो गई। जिसके चलते शोरूम से कार को बदलने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ता जीटी रोड स्थित मोटर शोरूम पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। परिषद के पदाधिकारी कार वापसी करने की मांग कर रहे हैं। जबकि शोरूम प्रबंधक रविंद्र सिंह का कहना है कि खरीदी हुई कार वारंटी में है। उसे ठीक कर दिया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद कार वापसी नहीं होती है। जो भी खराबी होगी, समय रहते ह्दु ठीक कराई जाएगी।

हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या में शामिल आरोपी को वसंत कुंज उत्तरी थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्रपाल के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज है। इसके पास से चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके साथ ही हाई सिक्वेरिटी वाले खराब नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिला का रहने वाला है। जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि महिपालपुर इलाके से एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। इस मामले में छानबीन करते हुए एसीपी सत्यजीत सरिन की देखरेख में एसएचओ राजीव मलिक की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलास की मदद से आरोपी के बारे में पता लगाने में कामयाब हुई। आगे की जांच में पता चला कि वह छह साल पहले जैतपुर इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल राम अवतार की गोली मारकर हत्या कर चुका है।

फिल्म सिटी के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम आज से होगा शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 अगस्त।

चिल्ला सीमा से महामाया पुल की तरफ जाते समय फिल्म सिटी के सामने सड़क चौड़ीकरण का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। अलग-अलग जगह करीब 350 मीटर हिस्से में सड़क चौड़ी होगी। काम पूरा होने में तीन से चार महीने का समय लग जाएगा। माना जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वालों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का जिम्मा सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एजंसी को दिया गया है। चिल्ला बार्डर से महामाया फ्लाईओवर की तरफ जाने वाली सड़क को सेक्टर-15 ए और 16 ए के बीच चौड़ा करने का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। यहां पर मौजूदा सड़क औसत 12.2 मीटर की बचती है। इसे सेक्टर-16 ए की तरफ फुटपाथ स्थानांतरित करते हुए 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-16ए की तरफ से भी नए सड़क जुड़ती है उस मोड़ को ओपी नए सिर से बनवाया जाएगा।

कोचिंग सेंटर मामला ‘बेसमेंट’ के चार सहमालिकों को नहीं मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजु बजाज चांदना ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं। इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के लिए ‘केवल वे जिम्मेदार’ नहीं हैं। अदालत ने कहा कि एक नागरिक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी ‘बेसमेंट’ के अवैध उपयोग के मामले को लंबित रखने वाले दिल्ली नगर



निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की भूमिका उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ कहती है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के लिए ‘केवल वे जिम्मेदार’ नहीं हैं। अदालत ने कहा कि एक नागरिक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी ‘बेसमेंट’ के अवैध उपयोग के मामले को लंबित रखने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की भूमिका उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ कहती है।

अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।

गांवों में तय समय में पूरा करें विकास कार्य : गोपाल राय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त

दिल्ली के गांवों में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। इस बाबत दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किए हैं। इस बार के बजट में दिल्ली के गांवों में विकास संबंधित कार्यों के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बजट से होने वाली परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा शुक्रवार को विकास मंत्री ने की। उन्होंने ग्राम विकास बोर्ड द्वारा सभी स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत रपट 10 सितंबर को होने वाली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

का गठन किया। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। इस बैठक में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बाढ़ एवं

नियंत्रण विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के अंदर पूरा करें। अब सभी स्वीकृत स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 10 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में विधायकों और ग्राम विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दिल्ली सरकार गांवों में सड़कों, पाकों,

नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।



नई दिल्ली के कम्पनी सभागार में शुक्रवार को नृत्य नाटक ‘कृष्ण’ के 48वें संस्करण में प्रस्तुति देते कलाकार।

निगरानी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली सरकार ‘एमपाक्स’ को लेकर सतर्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 23 अगस्त ।

दिल्ली में मंकीपाक्स के मामले आने की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार राजधानी में ‘मंकीपाक्स’ की स्थिति को लेकर कड़ी सतर्कता बरतने के साथ घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। केंद्र और (अन्य) राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी हमारी पैनी नजर है।

इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल

और बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल को एमपाक्स के संदिग्ध और सत्यापित मामलों के प्रबंधन के लिए पृथक कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया था। हालांकि उसने यह भी स्पष्ट किया था कि इस संक्रमण के किसी भी मरीज का पता नहीं चला है।

इस संक्रमण के सिलसिले में एलएनजेपी

अस्पताल को नोडल अस्पताल के रूप में नामित किया गया है, जबकि आपात स्थिति के लिए दो अन्य को भी तैयार रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके व्यापक प्रसार को देखते हुए मंकीपाक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है।

मौसम				
<i>तापमान</i>	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.0	33.0	32.2	32.6
न्यूनतम	26.7	26.8	26.4	25.7

जातिशी का दावा : 90 हजार बुजुर्गों के खाते में पहुंची पेंशन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछले पांच महीने से पेंशन में अपना योगदान नहीं देना का आरोप भी लगाया। आतिशी ने कहा कि शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90 हजार को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया। अन्य को भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्लीवालों के काम नहीं रुकने देगी, जिस तरह केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों को ये पेंशन दिलवाई है, उसी तरह लड़कर उनके रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे।

मंत्री ने दावा किया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में से दिल्ली सरकार 2,200 रुपए और केंद्र सरकार 300 रुपए का भुगतान करती है। पिछले पांच महीने से पेंशन

भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन
नई दिल्ली, 23 अगस्त (संवाददाता)। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध व विधवा पेंशन नहीं दिए जाने पर शुक्रवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में लाजपत नगर स्थित विभाग के कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पेंशन जारी करने का बयान दिया, जिसे भाजपा ने अपनी जीत बताया है।

लंबित थी क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अपना योगदान नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि योजना की शर्तें कुछ इस तरह की हैं कि केंद्र का पेंशन में कम योगदान होने के बावजूद एक लाख लाभार्थियों को पेंशन केंद्र से लंबित भुगतान के कारण अटकी रही।

आटो-टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन न कैब मिली; न आटो रिक्शा, लोग परेशान

आटो-टैक्सी चालक की मांग

टैक्सी चालकों की मांग है कि सरकार ओला-उबर तरीके की सरकारी पोर्टल बनाए और हमारे लोगों को शोषण से बचाए। ओला उबर रैपिडो मोबाइल एप जैसी अन्य कंपनियां के

गैर-कानूनी कारोबार के नेटवर्क पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस उमाही, बिना नंबर ई रिक्शा एवं पंजीकृत ई रिक्शा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध, दिल्ली की सभी प्रकार की टैक्सियों से निगम टोल टैक्स हटाए जाना, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चालक आयोग बनाए जाने की मांग है।

दिन कई जगह से आटो-टैक्सी में तोड़फोड़, टायरों की हवा निकलने जैसी घटनाएं हुईं। यमुना पार की तरफ से आने वाले कुछ आटो की क्षति पहुंचाई गई। उनके शीशे तोड़े गए। वसंत कुंज में हड़ताली आटो टैक्सी चालकों ने रैपिडो मोबाइल एप के जरिए गैर कानूनी तरीके से चलने वाली मोटरसाइकिलों को रोका।

उन्होंने कहा कि उनके यूनियन से जुड़े सैकड़ों लोग जो ओला उबर के जरिए अपनी

‘बूथ जीता, चुनाव जीता’ ही मूल मंत्र : योगी

गाजियाबाद, 23 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अतिआत्मविश्वास से बचें ‘आमजन के बीच रहकर संवाद और समन्वय स्थापित करें। कहा कि ‘बूथ जीता चुनाव जीता’ ही जीत का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए शासन की योजनाएं उपलब्ध कराई हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया, ‘बूथ पर काम करें। बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए।’ उन्होंने कहा कि ‘आरक्षण व संविधान के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब अफवाह फैलाई। उपचुनाव में विपक्षी दल फिर वोट मांगने आएंगे, उनके नेताओं से पुछिए कि आखिर एक-एक लाख कहाँ हैं। अपने वोट के जरिए उनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, ‘समाजवादी पार्टी-कांग्रेस ने आमजन को गुमराह करने की कोशिश की है। उनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए।’ उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आमजन को बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान की मूल प्रति को सिर पर रखकर संसद तक गए थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए विकास किया है।

गौतमबुद्ध नगर : डेंगू के लिए 13 स्थान संवेदनशील श्रेणी में

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 अगस्त।

गौतमबुद्ध नगर के 13 स्थान डेंगू के लिए संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें ग्रेनो वेस्ट का पूरा इलाका संवेदनशील घोषित किया गया है। वहीं, नोएडा के भी पांच स्थान इस श्रेणी में हैं। इन स्थानों पर तीन या इससे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले थे। मलेरिया विभाग ने ग्रेनो वेस्ट का पूरा इलाका, नोएडा के बरीला, सेक्टर-22, हरौला, सदरपुर, मोरना डेंगू के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। इनके अलावा कासना, सूरजपुर, सबौता, मायचा, दुजाना, बंबावड़ और जेवर का एक और गांव संवेदनशील सूची में है।

वहीं, नोएडा के निठारी, सेक्टर-8, 9, सेक्टर-62, और 51 को डेंगू के संवेदनशील इलाकों से अलग कर दिया गया है। पिछले

जनपद में अब तक डेंगू के 11 और मलेरिया के 34 मरीज मिले। सभी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।

साल यह इलाके संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में थे। जनपद में अब तक डेंगू के 11 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं, मलेरिया के 34 मरीज मिले हैं। सभी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जिला मलेरिया अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने बताया कि डेंगू के संवेदनशील क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जाती है। इन स्थानों पर एक भी मरीज मिलने की स्थिति में तत्काल दवाओं का छिड़काव, मरीज की स्थिति, इलाज समेत अन्य पहलुओं की जानकारी भी शासन को देनी होती है, ताकि डेंगू के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके।

अमन की राह

प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से स्वाभाविक ही सबको काफी उम्मीदें थीं। खुद प्रधानमंत्री भी वहां रवाना होने से पहले काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। जेलेंस्की ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वहां युद्ध की स्थितियों से उन्हें अवगत कराया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से युद्ध रोकने के उपाय तलाशने पर ही केंद्रित रही। यूक्रेन ने इच्छा जताई कि भारत शांति समझौते में सदा साथ रहे। हालांकि इस दौरान दोनों देशों ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अधिकारियों ने बताया कि इन समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर इसलिए भी दुनिया की निगाहें बनी हुई थीं कि शुरू से रेखांकित किया जा रहा है कि भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकवा सकता है। हालांकि भारत शुरू से ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील करता रहा है। यूक्रेन रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता।

यूक्रेन से पहले प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। तब जेलेंस्की ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए उनसे भारतीय प्रधानमंत्री के गले मिलने की आलोचना की थी। मगर अब वे भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने को लेकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री की अपीलों का यूक्रेन या फिर रूस पर कितना असर पड़ेगा। पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री पुतिन से फोन पर बातचीत करके या फिर आमने-सामने यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर चुके हैं। पिछले दिनों रूस जाकर भी उन्होंने पुतिन से यही अपील की थी। मगर अभी तक ऐसा कोई मौका नजर नहीं आया, जब रूस ने भारत की अपील पर संजीदगी दिखाई हो। शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान आमने-सामने बातचीत के बाद लगा था कि पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लिया है, मगर वहां से लौटते ही उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए थे।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं, उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का वाणिज्य और व्यापार बाधित हुआ है। वह चाहता तो है कि युद्ध विराम पर समझौता हो, मगर वह रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। रूस की शर्त है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता त्याग दे। दोनों में से कोई, किसी भी रूप में झुकने को तैयार नजर नहीं आता। ऐसे में बातचीत की मेज पर बैठने की सूरत बने भी तो कैसे, यही सबसे कठिन सवाल है। भारत के लिए भी बातचीत का रास्ता निकालना आसान नहीं है। मगर प्रधानमंत्री की दोनों देशों की बारी-बारी से यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व बंधुता का रास्ता तो बना ही है। उम्मीद की जाती है कि रूस और यूक्रेन थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए समझौते के लिए बीच के किसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाए।

अवरोध की सीमा

करीब छह महीने से शंभू सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सरकारी तंत्र को इसकी कितनी फिक्र है। जो काम सरकार को खुद अपनी ओर से करना चाहिए था, किसानों से संवाद करके शंभू सीमा को खोलने से लेकर अन्य मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसका रास्ता अदालत को बनाना पड़ रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों की शिकायतों का ‘हमेशा के लिए’ सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए जल्द ही एक बहुसदस्यीय समिति का गठन करेगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसे अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए अवरोधकों को एक हफ्ते के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। वहां प्रदर्शनकारी किसान इस वर्ष की फरवरी से अपनी मांगों के साथ डेरा डाले हुए हैं।

यह विचित्र है कि कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य कुछ मांगों का मसला इतना जटिल मान लिया गया है कि किसानों को इसके लिए छह महीने से सड़क पर धरना देना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार के साथ एक बैठक के बाद किसान राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमत हो गए थे। इस सिलसिले में शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा कि वे किसानों के साथ संवाद का रास्ता अपनाएं और उन्हें राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर और ट्रालियां हटाने के लिए राजी करें। मगर अब भी इससे संबंधित मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो निश्चित रूप से यह सरकार की नाकामी ही कही जाएगी। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इतने लंबे समय से शंभू सीमा पर एक व्यस्त सड़क के अवरुद्ध होने से आम लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सरकार के सामने यह प्राथमिक सवाल होना चाहिए था कि वह किसानों की मांगों पर विचार करते हुए, बिना देरी किए वहां आवाजाही को सामान्य बनाने पर सहमति बनाती।

चुनौतियों के बरक्स समाधान

विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की जरूरत है। मौजूदा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संधियां विफल हो रहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है।

रामानुज पाठक

अगले पांच वर्ष दुनिया के लिए संकट का काल है। अभी पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, दक्षिण एशिया में अशांति बढ़ रही है। दक्षिण चीन में भी चीन के आक्रामक रवैये से तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। ऐसे समय में विश्वव्यापी अशांति और आर्थिक चुनौतियों के बीच बहुत से देश संघर्षरत हैं। कठिन समय में कई देशों के बीच संबंध कटुतापूर्ण हैं। विश्व शांति के लिए विभिन्न देशों के मध्य मजबूत संबंधों की जरूरत है। मौजूदा विश्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संधियां विफल हो रहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है।

अगले पांच वर्षों में दुनिया के कुछ क्षेत्रों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे अधिक तीव्र और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। भविष्य में महामारियों का खतरा बढ़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, निजता और सुरक्षा के मुद्दे और गंभीर हो सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जानवरों से मानव में विषाणु का संचरण हो सकता है, जैसे कि सासं और एबोला आदि। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली के कमजोरी के कारण महामारी का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। जैविक हथियारों का उपयोग करके महामारी का कारण बनाया जा सकता है। अगले पांच वर्षों में विश्व में आर्थिक विषमता बढ़ने की संभावना है। इसके कई कारण हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ रही है, जिसमें कुछ देशों और समूहों को अधिक लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य को कम। प्रौद्योगिकी का विस्तार आर्थिक विषमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि अन्य को नहीं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण कुछ लोगों को आर्थिक अवसरों से वंचित किया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विषमता को बढ़ा सकती है, क्योंकि इससे निवेश और आर्थिक विकास प्रभावित होगा।

अगले पांच वर्षों में विश्व में राजनीतिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, और रूस जैसी महावक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। मध्य पूर्व, यूक्रेन, और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जारी संघर्ष बढ़ सकते हैं। आप्रवासन और शरणार्थी संकट के कारण राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। विश्व में प्रौद्योगिकी में निजता के लिए कई चुनौतियां होंगी। मसलन, डेटा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अधिक से अधिक डेटा आनलाइन हो रहा है। इस पर निगरानी एक बड़ी चुनौती होगी। कृत्रिम मेधा के विकास के साथ निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। ‘इंटरनेट आफ थिंग्स’ के विकास के साथ, अधिक से अधिक युक्तियां (डिवाइसेज) आनलाइन होंगे, जिससे निजता के मुद्दे और बढ़ेंगे।

असुरक्षित स्त्रियां

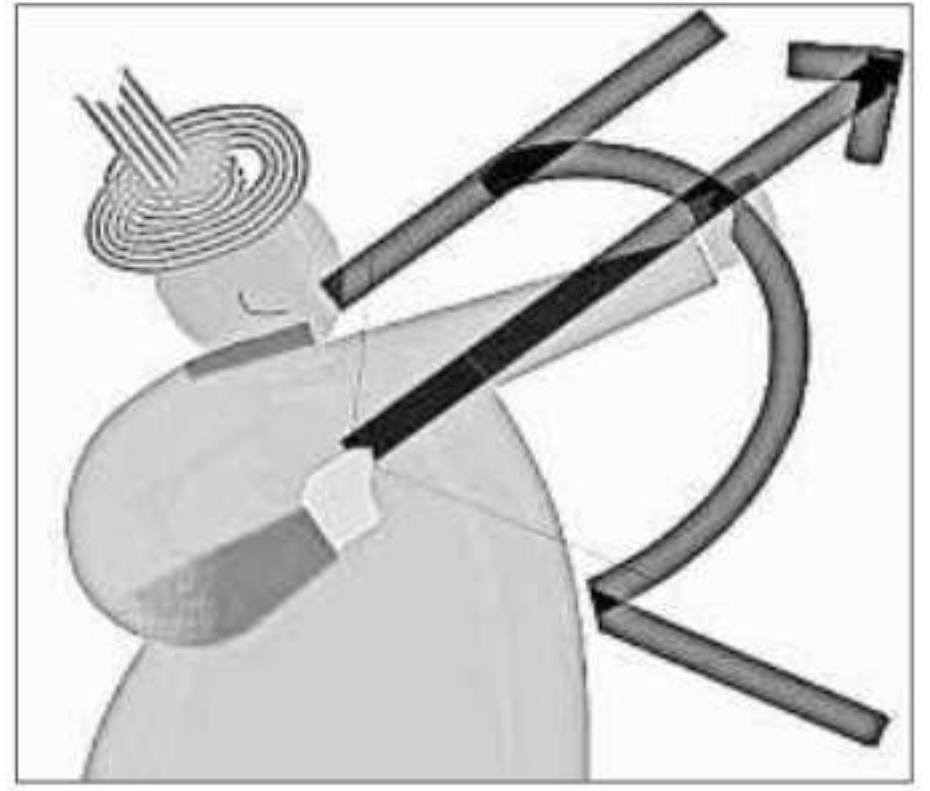
नरेंद्र भारती

कोलकाता में हुआ बलात्कार और हत्याकांड भारत जैसे सभ्य होने का दावा करने वाले देश के लिए एक और शर्म का विषय है। देश में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर सरकारों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। अब तो जैसे कोई भी विश्वास के योग्य नहीं रहा। अपने ही हैवान बन रहे हैं। बहू-बेटियां घर में भी असुरक्षित हैं। ऐसी घटनाओं से सरकारों के सुरक्षा संबंधी दावों की पोल खुल गई है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। कोलकाता की घटना पर लोगों का रोष अभी शांत भी न हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लोगों की नाराजगी फट पड़ी।

अपराध की गारंछ बदल जाती है, मगर तस्वीर नहीं बदलती। बेशक प्रतिवर्ष आठ मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, मगर ऐसे आयोजन मात्र औपचारिकता भर रह गए हैं। हर वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी, अत्याचारों का खान्दा किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, मगर धरातल पर सच्चाई की बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। यों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं, चांद तक अपनी कबलियत का परचम लहरा रही हैं। महिला सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून भी हैं, मगर व्यवहार में उनका कोई खौफ नजर नहीं आता। अगर वे कानून सही तरीके से लागू होते, तो ऐसे मामलों में इजाफा न होता। हर वर्ष के आंकड़े में महिलाओं के साथ दरिंदगी लगातार बढ़ी दर्ज होती है। 16 दिसंबर, 2012 को हुए निरंध्या कांड को लेकर हर भारतीय उद्बलित हुआ था। तब कानूनों की और कठोर बनाया गया था, और उम्मीद जगी थी कि महिलाओं के साथ हैवानियत की घटनाएं बंद हो जाएंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ।

तबसे अब तक लगातार बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ती गई हैं। दरिंदों की अराजकता बढ़ती ही जा रही है। 12 सितंबर, 2018 को हरियाणा के रेवाड़ी में उन्नीस वर्ष की एक मेधावी छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया गया था। 27 जून, 2018 को मध्यप्रदेश के भंडसौर में एक सात साल की नाबालिग स्कूली बच्ची से सामूहिक बलात्कार किया गया था। वह बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसके साथ हुई हैवानियत दिल दहलाने वाली थी। दरिंदों को जब तक ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलेगी, जो दूसरों के लिए सबक साबित हो, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगना कठिन रहेगा।

यह बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में लड़कियां कितनी महफूज हैं, इन घटनाओं से



सोशल मीडिया के विकास के साथ, निजता के मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। वैश्विक चुनौतियां कम करने के लिए, हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझना और इसके लिए कार्रवाई करनी होगी।

इसके अलावा अन्य उपाय भी करने होंगे। जैसे, जीवाश्म ईंधन के

अगले पांच वर्षों में विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनने का रहा है। भारत की संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है, और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके पास वैश्विक मुद्दों के समाधान में नेतृत्व करने की क्षमता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और आर्थिक विकास।

उपयोग में कमी और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना। वनस्पति विविधता का संरक्षण और वृक्षारोपण करना। जल संसाधनों का संरक्षण और

उनका संचय करना। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई करना। इन खतरों को कम करने के लिए, महामारी से लड़ने की तैयारी करनी और प्रतिक्रिया में सुधार करना होगा। वैश्विक सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना होगा। विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना होगा।

आर्थिक विषमता को कम करने के लिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना होगा, ताकि लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें। आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि लोगों को आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सके। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि आर्थिक विषमता और राजनीतिक तनाव को कम किया जा सके। संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी में निजता की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी होगी। डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि डेटा की सुरक्षा हो सके। प्रौद्योगिकी के विकास में निजता के अधिकार को शामिल करना, ताकि निजता के हनन को कम किया जा सके। लोगों को निजता के बारे में शिक्षित करना होगा, ताकि वे अपनी निजता की रक्षा कर सकें।

अगले पांच वर्षों में विश्व के लिए भारत का योगदान कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र बनने का रहा है। भारत की संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है, और यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके पास वैश्विक मुद्दों के समाधान में नेतृत्व करने की क्षमता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और आर्थिक विकास। भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह विश्व के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन सकता है।

भारत की संस्कृति में पर्यावरणीय चेतना है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत और विश्व के लिए एक प्रमुख पर्यावरण संरक्षण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक नेतृत्व करते हुए भारत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मसलन, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह वैश्विक शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह विश्व को आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है, जिससे यह विश्व को इस चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है।

भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे यह विश्व को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। वैश्विक शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे यह विश्व की शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकता है। भारत वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे यह विश्व की सांस्कृतिक विविधता में मदद कर सकता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नवाचार, और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होगी, जो भारतीय चिंतन 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना में निहित है।

बुजुर्गों की जगह

हमारे देश में बुजुर्गों को अत्यधिक सम्मान और महत्त्व दिया जाता रहा है और घर के सारे कार्य, तीज-त्योहार, शादी, सभी कुछ उनके मार्गदर्शन में होते थे। मगर अब वक्त बदलने के साथ-साथ बुजुर्गों के लिए न तो पहले जैसा सम्मान दिखता है और न महत्त्व। जो माता-पिता अपने जीवन भर का परिश्रम लगाकर अपनी संतानों का उज्ज्वल भविष्य बनाते थे, उनका भविष्य उज्ज्वल करने विदेशों में भेजते थे, अब बुढ़ापे में वही मां-पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में जीवन बिताना पड़ता है। हालांकि कुछ सुधार बुजुर्गों को भी अपने भीतर लाकर पीढ़ियों के अंतराल के अनुसार अपना व्यवहार बनाना होगा। हर छोटी-बड़ी बात में दखलअंदाजी और टोका-टोकी आज की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती। हमारे देश में गांवों की अपेक्षा शहरों में बुजुर्ग उपेक्षा का अधिक शिकार होते हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अपने बुढ़ापे की व्यवस्था समय रहते कर लेना चाहिए। संतानों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बेटा सिर्फ उनके कहे अनुसार ही चलेगा। बेटों को मां-पिता और पत्नी के बीच अच्छे से सामंजस्य बैठाना चाहिए।

- *विभूति बुपक्वा, खाचरोद, मप्र*

भूकम्प का जोखिम

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान सामने आने लगा है। बाढ़, भू और हिमस्खलन, आग के साथ ही भूकम्प बड़े विनाश की वजह बनने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान विश्व के अलग-अलग हिस्सों में भूकम्प के तीव्र झटके महसूस हुए हैं। भारत के सीमावर्ती देश भी भूकम्प से अक्सर तबाह होते हैं। इन झटकों की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। रिक्टर पैमाने पर बढ़ती तीव्रता इस बात का संकेत हैं

- *अमृतलाल मारु 'रवि', इंदौर, मप्र*

ढहते पुल

ब्रह्मरसात के मौसम में कुछ राय्यों में छोटे-बड़े पुलों के ढहने की खबरें सामने आती हैं। ऐसी घटनाओं से सरकार और संबंधित महकमे पत्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जितने पुल गिरे, उनकी समय रहते सुध ले ली गई होती, तो शायद हादसे न होते। हमारे देश की सरकारों और प्रशासन की आदत बन चुकी है कि दुर्घटना या हादसे के बाद नींद से जागना और फिर कुछ मुआवजे और चुके होंगे। आश्वासनों का मरहम लगाकर अगली दुर्घटना

प्रशिक्षण की बुनियाद

हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बात होती है, लेकिन पुरुषों के व्यवहार को नियंत्रित करने पर कोई बात नहीं करता है। लड़के रात में सड़कों पर उत्पात मचाते रहते हैं, लेकिन कोई मां-बाप उसे नियंत्रित नहीं करना चाहता। लड़कों को असीमित आजादी भी महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक कारण बनता है। उम्र के नाजुक दौर में लड़कों को विशेष निगरानी और सलाह की जरूरत होती है, लेकिन मां-पिता और शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करते हैं। बदलाव लड़कियों में भी आता है, लेकिन भारतीय माता-पिता लड़कियों पर निगरानी रखकर उसे नियंत्रित करते हैं और लड़कों को खुली छूट देकर उसे बर्बाद होने देते हैं। एक अभिवाक, शिक्षक और समाज के ये जिम्मेदारी है कि कोई नासमझ बच्चा गलत हरकत करे तो उसे नियंत्रित किया जाए। अन्यथा वे अपने साथ-साथ दूसरों की भी जीवन नष्ट करेंगे।

- *अशोष कुमार गुप्ता, जमुई, बिहार*

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष ने जनता को जिस शब्द से सबसे ज्यादा डराया, वह था गठबंधन। गठबंधन यानी कमजोर सरकार, जिसके फैसलों की कोई ‘गारंटी’ न हो। भाजपा सरकार को ‘गारंटी’ शब्द इतना भाया कि पारंपरिक घोषणापत्र को भी गारंटी बना दिया। ऐसा लगा कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आना उसके लिए आगे भी आने की ‘गारंटी’ है। अफसोस जनता ने गारंटीधारी सरकार को ऐसी हालत में सदन में भेजा जिसकी स्थिति की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।

बेबाक बोल

इति गारंटी

मुकेश भारद्वाज

केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि मौजूदा केंद्र सरकार के लिए किसी मुद्दे का आदि भी कांग्रेस होगी तो अंत भी कांग्रेस होगी। अश्विनी वैष्णव की वार्ता के समांतर सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह चलायमान थे। केंद्र सरकार के समर्थक सिंह को भारतीय नौकरशाही में विलंबित प्रवेश बता रहे थे। कुछ देर के लिए ही सही पता चल गया कि मनमोहन सिंह कितने बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान था। विलंबित प्रवेश प्रक्रिया जैसी चीज के बिना देश को वैसा योग्य अर्थशास्त्री मिलना मुश्किल था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके मूल्यांकन को लेकर उनके प्रति उदार रहेगा। लेकिन, वह ‘इतिहास’ इतनी जल्दी आएगा और भाजपा खेमे द्वारा लाया जाएगा यह तो सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। अफसोस कि केंद्र सरकार के खेमे ने जिस रणनीति के तहत उन्हें विलंबित प्रवेश प्रक्रिया का अग्रदूत बनाया वह अश्विनी वैष्णव के मीडिया बयान के चौबीस घंटे के अंदर फुसस हो गई। वैसे, राजनीति में अश्विनी वैष्णव का भी प्रवेश विलंबित प्रवेश प्रक्रिया से ही हुआ था। हालांकि प्रसारण मसविदा विधेयक के बाद वैष्णव को समझ आ गई होगी कि उनके बयान की कोई ‘गारंटी’ नहीं है। ऐसा पहले भी होता था कि सरकार अपने फैसले वापस लेती थी। लेकिन, एक प्रेस बयान में विलंबित प्रवेश प्रक्रिया के फायदे गिनाने के बाद फिर उन्हीं फायदों के खिलाफ खुशी-खुशी बोलना अब सरकार के मंत्रियों को और प्रवक्ताओं को बखूबी आ गया है। विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने विलंबित प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिया विज्ञापन वापस ले लिया। अब सरकार के प्रवक्ता इस वापसी को ही सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता बता रहे हैं।



शायद विज्ञापन तैयार करवाते समय गलती से कांग्रेस-काल वाली प्रतिबद्धता के पृष्ठ खुले रह गए होंगे क्योंकि राजग सरकार के मंत्रियों-प्रवक्ताओं के लिए कांग्रेस की नीतियों पर अधोषित अनुसंधान करना अनिवार्य है। लेकिन, सरकार कांग्रेस की नीति पर कांग्रेस की ही मुखालफत से परेशान हो उठे, एकदम से पलट जाए तो उसकी स्थिति को क्या कहा जाएगा ? हिंदी फिल्मों के अदालती दृश्य में घिसा-पिटा जुमला है, ‘आपकी दलील में दम है, लेकिन कानून सबूत मांगता है’। कुछ ऐसा ही राजनीति के साथ भी होता है। कोई राजनीतिक दल या राजनेता खुद के लिए कितना भी दावा कर ले कि वह मजबूत है, विपक्ष कितना भी आरोप लगा ले कि वह कमजोर है, लेकिन बिना सबूत तो बात बनती ही नहीं है। पिछली जून में लोकसभा के नतीजों के बाद कहा गया कि भाजपा सरकार कमजोर होकर लौटी है। पहला सबूत तो उसका ‘राजग सरकार’ हो जाना था। सरकार के समर्थक इसे मानने को तैयार नहीं थे। मगर, सरकार के तीसरे महीने में ही कमजोरी के निशान दिखाने की जो रफ्तार है उसे देख कर नहीं लगता कि कभी यह सरकार और उसके प्रवक्ता ‘गारंटी कार्ड’ लेकर घूमा करते थे। तब मजबूत थे इसलिए हर चीज की गारंटी देते थे। अब तो केंद्र की राजग सरकार रोज अपने कमजोर होने के नए-नए सबूत पेश कर रही है। वक्फ विधेयक पर विपक्ष के सवाल उठाते ही संयुक्त संसदीय समिति का पुनर्जन्म हो गया। सनद रहे, इससे पहले हर दूसरे विवादित विधेयक पर विपक्ष की यह मांग होती थी। लेकिन, तब केंद्र सरकार के अहंकार से लगता था कि संयुक्त संसदीय समिति इतिहास का हिस्सा है। अगर विपक्ष पूरी ताकत के साथ होता है तो सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। पिछले दस सालों से विपक्ष के पास ऐसी ताकत नहीं थी। अब स्थिति यह है कि गठबंधन सरकार के घटक

दल ही विपक्ष होने का माददा रखते हैं। बीते लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के नेता चुनावी भाषणों में जनता को गठबंधन सरकार के नाम से ऐसे डराते थे जैसे किसी फिल्म में मां कहती थी, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन, ऐसी डरावनी बातों से डरने के बजाय जनता ने सरकार को ही कह दिया सुधर जाइए नहीं तो गठबंधन आ जाएगा। और गठबंधन आ भी गया। वक्फ बोर्ड विधेयक पर गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों को आपत्ति नहीं थी। कुछ दल मुसलिम पक्ष से बातचीत चाह रहे थे। लेकिन, विपक्ष के वार से परेशान सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया। मलाईदार तबके को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शायद इस पर मतदान होता तो सरकार के पक्ष की जीत होती। इस मसले पर सरकार के घटक दल ही विपक्ष बन गए। कल तक खुद को ‘हनुमान’ कहने वाले सबसे पहले अपने कंधे से मजबूती की भक्ति का बोझ हटा कर

कमजोर कड़ी की मुखालफत में आगे रहे। प्रसारण विधेयक पर भी कदम पीछे हटाने से राजग सरकार की कमजोरी का सबूत प्रसारित हुआ। लेकिन, विलंबित प्रवेश प्रक्रिया पर जिस तरह से सरकार पलटी, वह तो ऐसा लगा जैसे उसने खुद ही उस कागज पर मुहर लगाई जिस पर लिखा था- यह सरकार कमजोर है। दशकों से चल रही प्रक्रिया पर भी कदम वापस कर सरकार ने इसे सुधार के लिए भेज दिया तो सवाल उठता है कि अब कितना सुधरिएगा ? नई-नवेली राजग सरकार की हालत की भविष्यवाणी करते हुए ही एक शीतल पेय की कंपनी का विज्ञापन था-डर सबको लगता है, गल्ला सबका सूखता है। सवाल है कि सरकार कमजोर क्यों दिख रही है और उसे डर किससे लग रहा है ? दो पारी तक राजग सरकार को हर मसले पर एकतरफा ‘गारंटी’ देने की आदत थी। विपक्ष के विरोध को तवज्जो नहीं देने की यह आदत अब भारी

नई-नवेली राजग सरकार की हालत की भविष्यवाणी करते हुए ही एक शीतल पेय की कंपनी का विज्ञापन था-डर सबको लगता है, गल्ला सबका सूखता है। सवाल है कि सरकार कमजोर क्यों दिख रही है और उसे डर किससे लग रहा है ? दो पारी तक राजग सरकार को हर मसले पर एकतरफा ‘गारंटी’ देने की आदत थी। विपक्ष के विरोध को तवज्जो नहीं देने की यह आदत अब भारी

संघ की पूछ शुरू

अभी तक तो खबरे सोशल मीडिया पर ही ज्यादा चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना बरहक़ीप बढ़ाया है। अब पार्टी में फैसले संघ की हरी झंडी मिलने पर ही होंगे। पार्टी अध्यक्ष का फैसला भी इसी वजह से लटका है। अब तो संघ के हस्तक्षेप का प्रमाण भी सामने आ गया है। संघ की पृष्ठभूमि वाले राम माधव को भाजपा ने जम्मू कश्मीर चुनाव का प्रभारी बनाया है। राम माधव कुछ साल पहले तक पार्टी के महासचिव थे। जम्मू कश्मीर में धारा-370 खत्म होने से पहले तक वही पार्टी के प्रभारी थे। इतना ही नहीं पीडीपी और भाजपा की साझा सरकार बनी तो उनके रणनीतिकार भी राम माधव ही थे। बाद में भाजपा को 2019 के चुनाव में बंपर बहुमत मिल गया और संघ के समर्थन की जरूरत खत्म हो गई तो राम माधव की भी छुट्टी कर दी गई। पर, अब भाजपा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। राम माधव के जम्मू कश्मीर के कई मुसलमान नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा पीडीपी के साथ तो जान नहीं सकती। ऐसे में राम माधव इन दोनों दलों से इतर दूसरे नेताओं का उपयोग करेंगे भाजपा के हित में। फिलहाल तो यही समझाया है संघ ने भाजपा के शिखर नेतृत्व को।

तलाश नए साथ की

घटक दलों के आंखें दिखाने से भाजपा परेशान तो जरूर है। लिहाजा पार्टी अब एक और भरोसेमंद सहयोगी की तलाश में जुट गई है। करुणानिधि के जन्म शताब्दी समारोह का चेन्नई में केंद्र सरकार ने आयोजन बिना मकसद तो किया नहीं। ऊपर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करुणानिधि की याद में जमकर कसौदे पड़े। इसी से इन कथासों को बल मिला कि भाजपा अब द्रमुक पर डोरे डाल रही है। द्रमुक की दिल्ली में कोई महत्वाकांक्षा न होना उस एक टिकाऊ और भरोसेमंद सहयोगी की श्रेणी में रखता है। लेकिन, द्रमुक का कांग्रेस और वाम दलों से गठबंधन है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने सूबे की सारी 39 सीटें जीती थी। इनमें 21 द्रमुक की हैं। भाजपा से हाथ मिलाने की अटकलों को हालांकि एमके स्टालिन ने खारिज किया है। पर राजनीति में नेता जो कहते हैं, हमेशा वैसा करते तो नहीं।

राजपाट

पोस्टर कुछ कहता है

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दल नए चेहरे पर दांव लगाना चाहता है। विधानसभा चुनाव के लिए अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन, जमीनी स्तर पर तैयारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही नए चेहरे की चर्चा में जुटे हैं। इसकी धमक दिल्ली में 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे मुख्य त्योहारों के साथ ही नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में नए नेता पोस्टर लगा रहे हैं, वही भाजपा के नेता भी सक्रिय हैं। जबकि कांग्रेस को पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की कमी को पूरा करने के लिए इस बार नए चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा, जिसकी खोज जारी है। त्योहारी पोस्टर ही आने वाले समय का संकेत दे रहे हैं।

अधर में हसरत

चंपई सोरेन की जरूरत क्यों पड़ रही है भाजपा को झारखंड में ? झारखंड में दो महीने बाद हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का भाजपा को सूबे में लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तक झामुमो उम्मीदवार से पिछला लोकसभा चुनाव हार गए। भाजपा ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को झामुमो से तोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ाया था। हेमंत सोरेन की पत्नी तो विधानसभा उपचुनाव जीत गई पर सीता सोरेन हार गई। जाहिर है कि भाजपा एक कद्दावर आदिवासी नेता के लिए हाताश है। चंपई सोरेन झामुमो के पुराने नेता उदरें। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से उनका आहत होना स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री होकर भी वे पार्टी नेतृत्व की खुली आलोचना कर रहे हैं। वे तीन दिन दिल्ली में भाजपा नेताओं से गुप्त बैठकें करके वापस झारखंड लौट गए। भाजपा का एक खेमा उन्हें पार्टी में लेने से कोई लाभ नहीं मिलने और उन्हें अलग पार्टी बनवाकर चुनाव में उतारने का पक्षधर है। पार्टी की इसी दुविधा ने चंपई को घर का छोड़ा न घाट का। उन्हें मुख्यमंत्री पद तो भाजपा भी देने को तैयार नहीं।

संकलन : मृणाल वल्लरी

अ से अति सि

यासत की बुनियाद पर खड़ा राष्ट्रवाद ‘अ’ के इर्द-गिर्द ठहर जाए तो बेबाक सवालों का उठना लाजिम है। हालिया सियासी माहौल में इन सवालों का जवाब हां में मिलना भी उम्मीद के माफिक है जो ‘अ से अति’ को सही साबित करता है। हाल के दिनों में मुक्त की सुरक्षा का मसला सियासत की सबसे कमजोर कड़ी बन कर उभरा है। मगर जब हिकाजत-ए-मुल्क के नाम पर किसी कंपनी या किसी एजेंसी को ही मुल्क मान लिया जाए तो सवाल पुछे जाएंगे। हिंडनबर्ग, सेबी और शेयर बाजार जैसे जुमलों से आधी से ज्यादा आबादी बेखबर है। बेजब शेरार बाजार की सीढ़ियों से सेबी और हिंडनबर्ग के झरखों से आधी-अधूरी तस्वीर देखने वाले भी पूरा मंजर देखने की दावेदारी लिए फिरते हैं। मगर जैसे ही शेयर बाजार से जुड़ी कंपनी या एजेंसी पर उठे सवालों पर कौमपरस्ती की चांदनी टांगी जाती है ‘अ और अति’ की दूरियां सिमट आती हैं। दो जून याद हो तो कुलांचे भरते शेयर बाजार की उछाल टीवी ने आवां को सियासत और बाजार के रिश्तों को यकीन में बदल दिया। यह रिश्ता ज्यादा गहरा हो जाता है जब सवालों को खतरा-ए-मुल्क करार देते सतरंगे पतंगों की डोर हुकूमत थाम लेती है। गौरतलब है कि हुकूमत की सरपारस्ती में सांस लेती कंपनी, एजेंसी या खास शक्तिशाल पर कोई आंच आए तो कौमपरस्ती की आड़ लेना सियासी बेबसी बन जाती है। बहरहाल जार्ज सोरोस का जिन्न खड़ा कर सरकारी निकायों की नाकामियों पर पड़े डालना खतरनाक नतीजों का इशारा तो नहीं ? -एमके मिश्रा, रातू रांची, झारखंड।

अंतरराष्ट्रीय तकाजा

हिंडनबर्ग का उद्देश्य व्यावसायिक हो सकता है। मगर दुनिया भर में काइनेटिशल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाएं भी हैं जो संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन पर नजर रखती हैं और दोषी देशों, संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का हर अंग पारदर्शिता, ईमानदारी और कानून सम्मत तौर-तरीकों से काम करे, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लेन-देन में मुश्किलें आएंगी। इसलिए अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता पर उठ रहे हर सवाल का जवाब देने से पहले मुकम्मल जांच जरूरी है। हो सकता है निष्पक्ष जांच के बाद आरोप झूठ निकलें और हिंडनबर्ग जो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है खुद उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। ध्यान रहे किसी एक का कृत्य



राष्ट्र पर भारी न पड़े क्योंकि राष्ट्रव्यवस्था अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आर्थिक रूप से अस्थिर राष्ट्र राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अस्थिर हो रहते हैं। सच्चा राष्ट्रवाद अर्थव्यवस्था को संदिग्ध और काले धन से मुक्त रखने में है न कि इससे जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने में। -बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

शत्रुता सेतु

देश जब पूरे वैश्विक बाजार का एक प्रमुख हिस्सा है तो सिर्फ हिंडनबर्ग जैसी विवादित एजेंसी द्वारा किए गए बाजारी रहस्योद्घाटन को हम आखिर क्यों अंतिम सत्य मान लें ? जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कुछ संदिग्ध गड़बड़ियां सह गतिविधियों की रवीकारोक्ति की तो किस परिस्थिति में याचकाना द्वारा मामले को अंतिम लक्ष्य बिंदु प्राप्त करने निमित्त कोर्ट को क्यों नहीं दुबारा संज्ञान हेतु निवेदन किया गया। पूरे वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव एवं हेराफेरी की जांच करने का ठेका हिंडनबर्ग ने जिस स्रोत से प्राप्त किया है क्या उसकी मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्राप्त है ? मोदी सरकार के एक भी लोकहित कार्य की तारीफ तो दूर संतुष्टि की सांस लेने से इनकार करते हुए जब विपक्ष शत्रुता सेतु पर सवार है तो किस मुह से वह उन मुद्दों की स्वतंत्र जांच की आस की उम्मीद करता है जब बहुत हद तक विश्व स्तर का एक गुट मोदी सरकार को उखाड़ने की उक्तक उक्तड़ा से सराबोर है। शेयर बाजार में यदि सेबी ने किसी कंपनी को स्थापित नियमों के विरुद्ध अपनी साख पर बटटा लगाया है तो विदेशी संस्था के बजाय इसकी न्यायिक जांच के स्वर विपक्षी क्यों नहीं उठाते, यह भी तो राष्ट्रीय भावना से ही ओतप्रोत है। नियामक संस्थाओं की साख पर सुलगते सवाल के तहरे निहितार्थ हैं, जिसे

पड़ रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो जा रहा है। विपक्ष जनता को बताने जाए कि फिलॉ फैसला कितना गलत है, उससे पहले सरकार खुद ही अपनी ‘गलती’ समझ कर उससे कदम पीछे खींच लेती है। मानो तय कर रखा है कि अभी भी विपक्ष के वजूद को नहीं मानेंगे, खुद ही विपक्ष से भी बड़े वाले विपक्ष बन जाएंगे।

तीसरी पारी में केंद्र सरकार इसलिए कमजोर हुई है क्योंकि जनता मजबूत हुई है। यह साबित हो चुका है कि इस देश में एक ही गारंटी चलती है-जनता की। जनता जब तक चाहेगी तब तक सरकार के रहने की गारंटी है। किसको कमजोर करना है, किसे मजबूत करना है, किसे दो साल की गारंटी तो किसे पांच साल की गारंटी के साथ सत्ता में भेजना है यह सब जनता ही तय करती है।

जनता ने राहुल गांधी को पांच साल की विस्तारित गारंटी के साथ सदन में भेजा है। अगर उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया तो जनता के पास उनके लिए चालीस का आंकड़ा पहले से है।

किसी सत्ता का लगातार दो बार तक आना बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन, सत्ता के इस दोहराव में जनता की भूमिका को नगण्य मान लिया गया। लगा, एक खास दल, विचारधारा के आगे जनता नतमस्तक है। राजनीति में किसी चीज का फतिहा जितनी जल्दी पढ़ लिया जाता है, सच यह है कि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। यहां तो जनचेतना के अंत की ही घोषणा कर दी गई थी और राजनीतिक दल ही जनता को गारंटी देने लगे थे। राजनीतिक शब्दावली से घोषणा और वादों की नभ्रता ‘गारंटी’ के अहंकार में बदल गई। आप चाहें तो राजनीतिक सत्य को भुला कर घोषणापत्र को गारंटी बोलें, लेकिन आपकी गारंटी तो जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी कि शब्दमाला में ‘ग’ से गारंटी के सामने आपका चित्र होगा या ‘क’ से कमजोर के सामने।

याद रहे कि ‘गारंटी’ का प्रमाणपत्र निर्माता की तरफ से दिया जाता है। नेता उस जनता को गारंटी देने का भ्रम पाल बैठे जो उनकी निर्माता है। आपने हर बात के लिए इतनी बार ‘गारंटी’ शब्द का इस्तेमाल किया कि खीझी हुई जनता ने आपकी सत्ता पर लिख दिया-नाजुक उत्पाद है, जरा ध्यान से इस्तेमाल करें।

सरकार को भी गंभीरता से लेते हुए दुष्ट और पानी में फर्क दिखाने का साहस दिखाना चाहिए। कारण यह भी पता लगना चाहिए कि विदेश में जब भी भारत के विरुद्ध कोई बात प्रचारित होती है तो देश का एक आंतरिक वर्ग उसकी हां में हां मिलाता है, क्या यही उनकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है ? -अशोक कुमार, पटना, बिहार।

निष्पक्ष जांच हो

अमेरिका की सर्टेबाज कंपनी हिंडनबर्ग ने जो हमारे देश के जाने माने अरबों गुपु पर हेराफेरी के आरोप लगाए हैं, उसने बैंकों और अन्य संस्थाओं को कठघरे में बैठाक खड़ा कर दिया है। लेकिन, हिंडनबर्ग ने जो आरोप अदाणी समूह पर लगाए हैं, उसकी भारत सरकार और रिजर्व बैंक को उचित और निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अदाणी समूह देश का बहुत बड़ा समूह है। इस समूह की वजह से लाखों-करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। इस समूह को कोई नुकसान होना है तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। -राजेश कुमार चौहान, जलंधर।

‘अ’ का आगमन

राजपाट में ‘अ’ का आगमन पड़ा। चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा चुनाव की घोषणा कर दी है। इस सूबे में लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस ने अजय माकन को यहां का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलग-अलग समूहों में बंटी हुई है। किरण चौधरी तो साथ छोड़ कर जा भी चुकी हैं। हरियाणा में भाजपा व्यवस्था विरोधी माहौल से जुड़ा रही है और उसे लोकसभा चुनाव में झटका भी लग चुका है। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल खराब है सिर्फ इस वजह से जीत नहीं मिल सकती। कांग्रेस को अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करनी है तो अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए एकता बनानी होगी।

-मीना धनिया सिरसपुर।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके डेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा ? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

शाह ने नैकां से गठबंधन पर कांग्रेस को घेरा

केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी से पूछे दस सवाल , कहा-अनुच्छेद 370 पर रुख स्पष्ट करें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नैशनल कांफ्रेंस (नैकां) के बीच गठबंधन होने पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर हमला किया। साथ ही कांग्रेस से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह अनुच्छेद 370 बहाल करने के ‘अब्दुल्ला परिवार’ के चुनावी वादे का समर्थन करती है। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शाह ने ‘एक्स’ पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नैकां के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। शाह ने नैकां के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, ‘क्या



कांग्रेस नैकां के जम्मू-कश्मीर में फिर से ‘अलगा इंडे’ के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नैकां के निर्णय का समर्थन करती है?’ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने यह सवाल भी किया

जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली बैठक सात से आठ सीट पर प्रत्याशी को लेकर सहमति बनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुआई में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) पहली बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सात से आठ विधानसभा सीटों के नाम पर सहमति बनी है। राज्य में तीन चरण में मतदान होना है और यहां कांग्रेस पार्टी इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत समिति के अन्य सदस्य भी शामिल रहे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी में पहले नौ सीट

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बंद के आह्वान पर रोक लगाई

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में राजनीतिक दलों या अन्य लोगों की ओर से प्रदेय बंद का आह्वान करने पर रोक लगा दी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (एमवीए) ने शनिवार को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोकरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

उधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से दो याचिकाएं दायर कर महाराष्ट्र में बंद के आह्वान को चुनौती दी गई है। इन पर सुनवाई

पेज 1 का बाकी यूक्रेन और रूस साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशें

है और हम मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की की मौजूदगी में अपनी रूस यात्रा और उस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई वार्ता का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी रणभूमि में नहीं होता है। समाधान केवल बातचीत, संवाद और कूटनीति के माध्यम से होता है और हमें समय बर्बाद किए बिना उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की सत घंटे की यात्रा के बाद कोव से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ ‘सार्थक वार्ता’ की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यव्भिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया। कई बैठकों में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि यूक्रेन की उनकी यात्रा ऐतिहासिक रही। वह भारत-यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने के उद्देश्य से आया है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी

नेपाल में भारत की बस नदी में गिरी, 27 की मौत

रिश्तेदार थे। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार 43 यात्रियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘पोखरा से काठमांडो जा रही एक भारतीय पर्यटक बस में लगभग 43 भारतीय सवार थे। यह बस शुक्रवार की मर्यादावी नदी में गिर गई।’ इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में भारतीय यात्रियों को ले जा रही एक बस के नदी में गिर जाने के बाद घटना का संज्ञान लेते हुए राहत पहुंचाने के लिए एक उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को नेपाल भेजा है और एक अधिकारी (एडीएम) को नेपाल-यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने के उद्देश्य से आया है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी

करते हुए पीठ ने कहा, ‘हम राजनीतिक दलों या किसी भी अन्य व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। राज्य सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी।’ राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत में दलील दी कि बंद का आवाहन अवैध है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि जनता या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी, लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। पीठ ने सराफ से पूछा कि सरकार ने क्या कोई एहतियाती कदम उठाए हैं और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है? उस पर सराफ ने कहा कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कि क्या कांग्रेस, कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? नैकां के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को एलान किया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा अब्दुल्ला के आवास पर नैकां के नेतृत्व के साथ बैठक किए जाने के बाद यह घोषणा की गई है।

शाह ने पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के नैकां के निर्णय पर भी कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी सामने आया है, क्योंकि नैकां ने दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने का वादा किया है। उन्होंने

तारिक हमीद कर्रा, प्रदेश प्रभारी भरत सिंह सौलकी और राज्य में सीईसी से संबंधित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

आयोग की घोषणा के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 18, सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को तीन चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के बाद पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, इस चरण में 24 सीट शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में एक लंबे समय के बाद मतदान कराया जा रहा है और धारा 370 हटने के बाद यह पहला मतदान होगा। आयोग ने पहले ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य स्थिति का जमीनी आधार पर जायजा ले चुका है और इसके लिए पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर चुका है।

केवल अस्थायी होने के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इन कारकों पर उचित विचार किए बिना केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। पीठ ने कहा कि इस दृष्टिकोण से

पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य पर्वत’ ‘तख़्त-ए-सुलिमान’ और ‘हरि पर्वत’ ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाने जाएं? शाह ने यह सवाल भी किया कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर ‘पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों’ के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा, ‘क्या कांग्रेस पार्टी नैकां के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है।’ शाह ने कश्मीर को स्वायत्तता देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ‘विभाजनकारी सोच और नीतियों’ पर भी कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि नैकां ने सौमवार को जारी अपने घोषणापत्र में 12 ‘गारंटी’ की घोषणा की, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरण के तहत चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूर को होगा। नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।



वार्ता नई दिल्ली में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में बात करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी।

कर्मचारियों का ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की सेवा करने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों और सुरक्षा से वंचित है।

न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि कर्मचारी, जिसे मुख्य रूप से नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया, नियमित कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियों को लंबे समय तक निभाता है, नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्राप्त करता है तो ऐसा कर्मचारी अब एक अस्थायी कर्मचारी नहीं रहता है और उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं ने एसएफएफ मुख्यालय स्थापना संख्या 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन किया। नौकरी के कार्यों में यह समानता अपीलकर्ताओं की स्थिति और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है, यह सुझाव देते हुए कि अंतर वास्तविक से अधिक औपचारिक हो सकता है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि अपीलकर्ताओं को वैध और पांचवें वेतन आयोग से महत्वपूर्ण तत्वों का विस्तार सरकारी कार्यों में नियोजित होने की उनकी दलील को और पुख्ता करता है।

विपक्ष ने एकता-सद्भाव से भाजपा का अहंकार तोड़ा : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की विचारधरा ने एकता –सद्भाव से भाजपा का अहंकार तोड़ा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नफरत की मोहब्बत से हराएंगे। राहुल गांधी का इशारा आने वाले चुनावी राज्यों की तरफ था। यह वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भाजपा की विचारधारा को तोड़ा दिया है। आप कार्यकर्ता और पार्टी के बम्बर शेर हैं। आप कांग्रेस पार्टी का झंडा हो।

उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर नफरत की मोहब्बत से हराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री पहले छाती फुलाकर आते थे और अब उनका तरीका बदला है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि भाजपा को किसने हराया। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा को हराया। राहुल गांधी ने इसके जवाब

में कहा कि नहीं भाजपा को विपक्षी गठबंधन की एकता, विचारधारा और मोहब्बत ने हराया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेकिन साफ बता दिया कि आप अपने आप को जो सोचते हो, वह आप नहीं हो।

इसके अतिरिक्त पूर्व कांग्रेस सरकार में मजदूरों के लिए शुरू की गई मनरेगा की जानकारी भी शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे ने जारी की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मनरेगा योजना की शुरुआत की गईथी और इसके तहत मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी गई थी। इस योजना का लाभ आज देश के गरीब तबके को मिल रहा है। इस समय योजना के तहत 13.3 करोड़ लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। बावजूद इसके मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार ने वीते दस साल का सबसे कम बजट जारी किया है और इस बार केवल 1.78 फीसद बजट ही मनरेगा के लिए जारी किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जबकि इस समय में महंगाई की सबसे अधिक मार शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर पड़ रही है।

राकांपा (एसपी) से मुख्यमंत्री पद का कोई इच्छुक नहीं : शरद पवार

पुणे, 23 अगस्त (भाषा)।

शिवसेना (यूबीटी) द्वारा विपक्षी महाविकास आघाडी (एमवीए) पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने का दबाव बनाए जाने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरदचंद्र पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके बजाय उनकी पार्टी राज्य में सरकार बदलने की ओर ध्यान दे रही है।

पवार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर 27 अगस्त को बैठक होगी। उन्होंने बताया कि पहले यह बैठक 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए कथित यौन शोषण के कारण इसे टाल दिया गया था। शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए द्वारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करने पर जोर दिए जाने, जबकि कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा, ‘जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है तो हमारे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।’

उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी से किसी की भी (मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने में) दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ सरकार बदलना चाहते हैं। हम एक ही मंच पर (अन्य एमवीए सहयोगियों के साथ) रहकर राज्य के लोगों को बेहतर प्रशासन देना चाहते हैं।’ पवार ने चुनाव से पहले कहा कि सभी का ध्यान लोगों को सत्तारूढ़ महायुति के अलावा दूसरा विकल्प प्रदान करने पर होना चाहिए।

बीएनएसएस की धारा 479 विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 देशभर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भले ही अपराध एक जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किया गया हो।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि बीएनएसएस की धारा 479, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का स्थान लिया है, सभी विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से प्रभावी हुए थे। शीर्ष अदालत ने इस अभिवेदन पर गौर किया और देशभर के जेल अधिकार्यों को निर्देश दिया कि वे प्रावधान की उपधारा में उल्लिखित अवधि का एक तिहाई पूरा होने पर संबंधित अदालतों के माध्यम से विचाराधीन कैदियों के आवेदनों पर कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि ये कदम यथाशीघ्र, संभवतः तीन महीने के भीतर उठाए जाने चाहिए।

मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने इससे पहले पीठ से कहा था कि विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित धारा 479 को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और इससे जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। शीर्ष अदालत अक्टूबर 2021 से जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, जब उसने इस समस्या का स्वतः संज्ञान लिया था।

सिद्धरमैया के साथ कांग्रेस, आरोपों को सरकार गिराने का प्रयास करार दिया

नई दिल्ली, 23 अगस्त (ब्यूरो)।

कांग्रेस नेतृत्व ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मामले में शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का समर्थन किया और कहा कि ये आरोप राज्य में उसकी सरकार को अस्थिर करने तथा सरकार की विधिन् ‘गारंटी’ को रोकने का प्रयास है, लेकिन पार्टी नहीं झुकेगी और न्यायपालिका में तथा जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेगी। शुक्रवार को सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भूमि घोटाले मामले में राज्यपाल की जांच मंजूरी के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की ।

 एसेट रिक्तस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत अर्सिल कार्यालय: रुबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बंगला मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400 028 शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टेंड मोल, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली पीओ : 110058 वेबसाइट: https://auction.arcil.co.in; सीआरएन-U65999MH2002PLC134884
--

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संघर्षियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शर्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से विक्री के लिए सार्वजनिक सूचना एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटरी/बंधककर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट (‘अर्सिल’) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एसेट रिक्तस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (‘पंजीकृत अप्रानमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय आगंत के एसाइनमेंट के अनुसार’) के पास बंधक/प्राभति नीचे वर्णित अचल संघर्षियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संघर्षियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के संदर्भ में आगे व्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली के लिए अतिरालइन ई-नीलामी के माध्यम से “जैसा है जहां है”, “जो है यही है”, “जो कुछ भी है वही है” तथा “आश्रय रहित आधार” पर बेचा जायेगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटरी/बंधककर्ताओं के नाम	लैन नं. एवं विवरण बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी नोटिस दिनांक 13.09.2022 के अनुसार बकाया राशि	कबजे का प्रकार तथा तिथि	तिरिछा तिथि	सम्पत्ति का प्रकार तथा क्षेत्रफल	जमा धरोहर राशि (इंग्रैडी)	आगति मूल्य	नीलामी की तिथि तथा समय
1	1. मैनम स्ट्रीलस लिमिटेड 2. ईश्वर चन्द्र सिंहल 3. उतत जिल्ल 4. मैनम स्ट्रील एंड पॉवर लिमिटेड 5. जी.आर. एल्लिएसएल प्रा.लि. 6. आई.सी. जिल्लर एंड दंस (एलएफएल)	401FSL14252493 तथा बकाय फाईनेस लिमिटेड (‘बीएफएल’) 042-डी-ट्रस्ट	अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट	र. 7, 273, 927,579.89/- (रुपये दो करोड़ सित्तर लाख बानने हजार नववीं पैसे मात्र) तिथि 22-11-2021 + उस पर धारी व्याज + पक्षिक व्यय	भौतिक 28-06-2024 तक	02.09.2024	याणिम्यक एवं सुरर एतिया 2850 वर्ग फीट	र. 57,50,000/- (रुपये सैतार लाख पचास हजार मात्र)	र. 5,75,00,000/- (रुपये पंच करोड़ पित्तराल लाख मात्र)	तिथि 26-09-2024 को 12.00 बजे अप.

नीलाम की जा रही प्रतिभूत संघर्षि का विवरण: मैनम इटनेशनल लिमिटेड के इसके निदेशक आई.सी. जिल्लर के माध्यम से स्वामित्व वाली संघर्षि: वसुध समर्पि वृष्टि नं. 312 तथा 313 का समरत भाग, तीसरी मंजिल, छत तक तथा छत के अधिकार रहित, समुष्पि समर्पि निमग सं. सी-1, 2 तथा 3 का भाग, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर अग नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली- 110034 मैनम इटनेशनल लिमिटेड के नाम पर इसके निदेशक आई.सी. जिल्लर के माध्यम से, उत्तर : मेन रोड, दक्षिण : प्लांट नं. सी-9, पूर्व : समर्पि सं. 2, 3 एवं 4 (एच.बी. दिवन टॉवर के नाम से) पश्चिम : समर्पि सं. सी-4, 5 एवं 6 (अवधाल लेलिमियम जोन के नाम से) सीमाएं: उत्तर में: लल्लू का घर, दक्षिण में: खुला स्थान आसम, पूर्व में: खुला स्थान आसम, पश्चिम में: मुनीर का घर।

अर्सिल को ज्ञात लिखत मुद्रपत्रे	नित	अर्सिल को ज्ञात ऋणभार/बकाय	नित
बोली जमा करने की अनिवार तिथि	नीलामी से 2 घंटे पहले उसी दिन	बोली वृद्धि राशि :	बोली दस्तावेज में लिखित के अनुसार
के नाम में बैला होने वाला डिमांड ड्राफ्ट	ट्रस्ट नाम नीलामी में उल्लिखित के अनुसार	दिल्ली में 042	
आरटीबीएस विवरण			
	बैंक का नाम : एचएफडीसी बैंक/ट्रस्ट का नाम : अर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो-042-डी-ट्रस्ट, खाता संख्या: 57500000730812/आरटीबीएस/एनईएफडी आईएफएफसी : HDFC0000542, शाखा : कर्माला मिसस कम्पाउंड, सेनापति बाघट मार्ग, लोहार रोड, मुंबई 400013	शैलेश गावकवाड़ - 9867929121 (shailesh.aikwad@arcil.co.in) मोहेश बोंगेग - 9004173256 (mahesh.banaraea@arcil.co.in) विक्रम सिंह तेंवर - 8860122299 (vikram.tanwar@arcil.co.in)	
सम्पत्क स्वतित्व का नाम तथा नम्बर/ई-मेल आईडी	शैलेश गावकवाड़ - 9867929121 (shailesh.aikwad@arcil.co.in) मोहेश बोंगेग - 9004173256 (mahesh.banaraea@arcil.co.in)		

नियम एवं शर्तें :
1. नीलामी विक्री वेबसाइट <https://auction.arcil.co.in> के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा तथा बोली दस्तावेज के नियम एवं शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी (‘‘एजेंट’’) /एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, एंजेंट बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रक सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल बोली/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार प्रभित्भूत पर्सिपसिफि को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करवाने के लिए भुगतान किए जाने वाले सभी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टंपि शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले वैधानिक बकाया आदि सहित प्रभित्भूत पर्सिपसिफि को प्राभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, प्रभित्भूत पर्सिपसिफि के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच/उचित परिश्रम करना चाहिए। नीलामी विभापन एआरसीआईएल एवं किसी भी प्रभित्भूतदाता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करती है और न ही करेगा। अर्सिल का प्राधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समयाच पत्र में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ब्यापार एग एट्, हालांकि अधोहस्ताक्षरतां किसी भी बुटि, गलत बयान या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया देय राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस विक्री नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के तहत उपर्युक्त नीलामी विक्री के आयोजन के बारे में एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि किसी भी कारण से ऊपर निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो अर्सिल को नियमों और अधिनियम के नियम 8 (5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से प्रभित्भूत संघर्षि को बेचने का अधिकार है।
स्थान: दिल्ली/तिथि : 24.08.2024

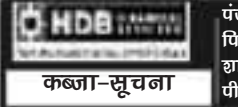
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

एसेट रिक्तस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

 HOUSING FINANCE LIMITED		कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत एवं कार्परेट कार्यालय :- 502, उत्तर-ए, पेरिगुलाल विजेंस गार्ड, सेनापति बाघट मार्ग, लोहार रोड, मुंबई-400013 सर्विकत कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूना रोड, राजेन्स प्लेस, नई दिल्ली-110060		
परिशिष्ट –IV-क अधिनियम 8 (6) और 9(1) का परंतुक देखें, अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना				
वित्तीय आसियायों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवर्ती, 2002 के नियम 8 (6) तथा 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आसियायों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सर्व सामान्य को और विशेष रूप से कर्जदार/गारं(टी) को सूचना दी जाती है कि प्रयाप्तभूत लेनदार के पास बंधक /प्राभरता निम्नवर्तीपत अचल सम्पत्तिए, जिसका प्रबलित/भौतिक कब्जा कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड, प्रयाप्तभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों की तरफ कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड, प्रयाप्तभूत लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित शर्तियों को ‘जैसी है जहां है’, ‘जैसी है जो है’ तथा ‘जो भी है वहां है’ आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, ईंग्रैफी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।				
क्र. सं.	कर्जदार/गारं(टी) का नाम 2 बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	1 ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2 ईंग्रैफी जमा करने की अंतिम तिथि	1 सुरक्षित मूल्य 2 सम्पत्ति की ईंग्रैफी 3 वृद्धि मूल्य
1.	1. श्री सुशील कुमार धामा (कर्जदार) 2. श्रीमती सुदेश, 3. मैसर्स जीधिका धामा एट्टएडवाइज (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. LNMECH0A000021458 (पुराना)/ 50600000895166 (नया) रुपये 18,67,516/- (रुपये सोलह लाख सड़कर हजार पांच सौ सोलह मात्र) 20-08-2024 + आगे लागू व्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि परिमाण 224 वर्ग गज (187.286 वर्ग मीटर) पर निर्मित मकान, खसरत नंबर 619 निम्न. धाम केडेटाहाजीपुर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गांधियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, चौहदरी निम्नानुसार – पुरव : गली पश्चिम : अन्य का पर्वट, उत्तर : अन्य का पर्वट, दक्षिण : शिव मंदिर	1 ई-नीलामी की तिथि : 27-09-2024 (अप्र 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2 ईंग्रैफी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-09-2024 3. निरीक्षण की तिथि : 25-09-2024	1. सुरक्षित मूल्य रु. 41,80,000/- (रुपय इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) धरोहर राशि जमा : रु. 14,80,000/- (रुपय चार लाख अठारह हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 10,00,00/- (रुपय दस हजार मात्र)
2.	1. श्री चंदर बीर (कर्जदार) 2. श्रीमती नीलाम (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. LN300000000887066 (पुराना)/ 05030000847229 (नया) रुपये 11,74,187/- (रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ सताती मात्र) 20-08-2024 + आगे लागू व्याज।	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 8 का प्लॉट भाग, क्षेत्रफल परिमाण 50.11 वर्ग मी. यानी 41.91 वर्ग मीटर, खसर नंबर 76 निम का अग्र, मगराचौकिका काउंड के बाहर, ग्राम गटला, न्यू कालोनी, गढ़ रोड, परगना तहसील एवं जिला हाउस, उत्तर प्रदेश-245101, चौहदरी निम्नानुसार – पुरव : प्लॉट नंबर 8, पश्चिम : प्लॉट नंबर 8 का रोप भाग, उत्तर : 10 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	1 ई-नीलामी की तिथि : 27-09-2024 (अप्र 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2 ईंग्रैफी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 26-09-2024 3. निरीक्षण की तिथि : 25-09-2024	1. सुरक्षित मूल्य : रु. 8,00,000/- (रुपय आठ लाख मात्र) धरोहर राशि जमा : रु. 80,00,00/- (रुपय अस्सी हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 10,00,00/- (रुपय दस हजार मात्र)

विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड, प्रयाप्तभूत लेनदार, की वेबसाइट www.capriglobal.in/auction में उल्लेख प्राप्त किया गया लिंक देखें।
ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-
1. समर्पित ‘जैसी है जहां है, जो भी है वहां है’ तथा कोई बापसी नहीं आधार” पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं वारिप्टिफिके के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आसित के विवरण (उल्लेखनर) के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना में निर्दिष्टित सीमा एवं परिमाण) प्रभित्भूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सहीरित किए गए हैं तथा प्रभित्भूत लेनदार किसी बुटि, निष्पादनकार अथवा लेलिमयन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं मात्र निम्न हो सकता है।
3. प्रभित्भूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसामान्य को अपने बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा वह प्रभित्भूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सहीरित किया गया है तथा प्रभित्भूत लेनदार किसी बुटि, निष्पादनकार अथवा लेलिमयन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं मात्र निम्न हो सकता है।
4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर अपना ऑनलाइन टाइमर मोबाइल एप के माध्यम से ‘बोलीदान इलेक्ट्रॉनिक मोड’ द्वारा होगा, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए नीलामी की समुष्पि प्रक्रिया की व्यवस्था एवं संचाल्य करेगा।
5. बोलीदाता/बोलीदान के लिए अनिवार पंवन के प्यान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोलीदाता को स्वयं बकाय होनी। प्रभित्भूत लेनदार/सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिकीबिक्री, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश आदि, ग्रावर कनेक्श इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. संभर्षित बोलीदाता ई-नीलामी को संभव में विस्तृत विवरण, हस्तागत प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद (मैसर्स नंबर 07980136880फोन136887), भी ताम कुमार मोहाइल नंबर 800-002-3297/79-61200559, ई-मेल : rampandusa@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. इष्टभूत बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर मापित अधिन में करवाना होगा तथा कुल्ल आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इष्टभूत बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलने ही इष्टभूत हस्ताके बरल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इष्टभूक बोलीदाता को एक प्रतिपत्र ईंग्रैफी, जोकि मुसलि मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) ‘कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफडी/आरटीबीएस के माध्यम से 26-08-2024 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इष्टभूत बोलीदाताओं को विधिवत प्राप्त गया बोली पत्र (मैसर्स <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है) ईंग्रैफी हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक रीजर्वेड तिकाफे में प्रस्तुत करना चाहिए। जोपरि प्रभित्भूत अधिकारी, कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी, प्लॉट नंबर बी.ई. द्वितीय तल, पूना रोड, राजेन्स प्लेस, नई दिल्ली-110060 को अधिकृत 26-08-2024 के अग 03.00 बजे तक भेजना जा सकता है। रीजर्वेड तिकाफे पर ‘कर्जदार नाम’ की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नम्बर – (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली सौधीकृत किया जाना चाहिए।
10. ईंग्रैफी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनकें द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करत तथा सौर्य बोलीदाताओं (जिनकें द्वारा अपनी बोलियां सुरक्षित मूल्य से अधिक रकम की गई है तथा प्रभित्भूत लेनदार द्वारा निर्दिष्टित ईंग्रैफी की गई है) को विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्वोमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करतें ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति केवल उसी योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्भूत उच्छायाओं को से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के अंतिमति विस्तार होने अर्थात् ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली अपर हर बार सख्त 10 मिनट अपर बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वासर नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई घुंजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसकें द्वारा दी गई बोली मानी जाएगी।
13. ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसकें द्वारा उद्भूत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तिकाफे ई-मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी, प्लॉट नंबर बी.ई. द्वितीय तल, पूना रोड, राजेन्स प्लेस, नई दिल्ली-110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में कार्यवाह, कर्वालय/प्लॉट नंबर बी.ई. द्वितीय तल, पूना रोड, राजेन्स प्लेस, नई दिल्ली-110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई-नीलामी प्रक्रिया में कार्यवाह किया जा सकें।
14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (इंग्रैफी सहित) बोली उसकें पक्ष में घुंजे पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15 दिन के भीतर कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/बैंक ऑर्डर/एनईएफडी/ आरटीबीएस/बैंक द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी केला द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान निरात अवधि के भीतर करने में सक्ष्म की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशिया (इंग्रैफी सहित) जमा कर दी जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतु रखी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुप्रेष पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम बुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बरर टीएएसए (बिक्री राशि) से अति करनी होगी तथा टीडीएसए सॉफ्टिकोफ्ट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पुरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएसए कटने के बाद), ईंग्रैफी सम्पाद्योक्ति करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिक स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अपर करनी होगी, जिसमें आवश्यक रखने पर जमा की गई धरोहर जमा जमा कर ली जाएगी।
18. मुद्रास्वित्प/बकाय कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां समर्पित से संभर्षित सभी कारकी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उत्पन्न द्वारा पूर्व जमा मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतु लागू करनी प्रभार तथा अन्य अनुभूती प्रभार नीलामी केला को वहन करने होंगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यावली प्रस्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिक्री कार्याक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रस्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
22. प्राधिकृत अधिकारी का नियम अंतिम, कर्तव्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
23. सभी बोलीदाता, जिनकें द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें एवं एवं समझ चुकें हैं तथा उनके अधीन कार्य होंगे।
24. सम्पत्ति में रखी बल वस्तु (यदि कोई) इस बिक्री की अवधि के अंत में हटाई नहीं जाएगी।
25. कृपया नोट करें कि डीआईएन-2, दिल्ली के समक्ष एक प्राधिकृत अधिकारी आदेशन एएसए नंबर 33/2024 के माध्यम से जारी है। क्र. सं. 1 हेतु
26. अधिकृत विवरण तथा पुरातना के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड : सुधी लाला सिंह मोहाइल नंबर 8996755043 जो सम्पर्क करें और अपने पुरातना के लिए सुधी करपण चेतननाथ – 77380 39346 से सम्पर्क करें।
27. यह प्रमाणपत्र अत्र अत्र खाते के कर्जदार/बंधकदार/गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6), तथा 9(1) के अन्तर्, उपनिर्धारित तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के संबंध में 30 (तीस) दिन का कानूनी नोटिस देगा।
विशेष अनुदेश/शर्तियां : बोलीदाताओं को अनिवारि अथवा बर्णों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में स्थानात होगा। ना तो कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता को और से किसी विफलता/कमी (डिफ़ूट बिक्रलता, इंटरनेट बिक्रलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के अ्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैंकअप पॉवर आवृत्ति द्वारापि केडी अधिकृत व्यवस्थापक/बिक्रल तैयार करें, ताकि वे किसी भी आकस्मिक क्लवकट से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
स्थान: दिल्ली/एनसीआर तिथि : 24-अगस्त-2024

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) कैंडी ग्लोबल हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड

 पंजीकृत कार्यालय: पश्चिम, हुस्की जमिनि, डॉ. मर्दाने रोड, नारायणपुर, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड 380009 शाखा कार्यालय: एएडीबी फाइनॅसिजल सर्विसेज लिमिटेड, खसरा नंबर 47, अंनैक पर्वत क्लुब के पीछे, विमानपुरी दिल्ली 110018
कक्षाओं-सूचिका

जनकिक, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 64) के तहत **एचएफडीसी फाइनॅसियल सर्विसेज लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत शर्तियों के प्रयोग के तहत ऋणीयों जैसा कि नीचे दिया गया है, को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान की तारीख से लेकर वास्तविक तक सभी लागू, शुल्कों और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणीय/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। एतद्वारा ऋणीय/सह-उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त नोटिस के दिनांक 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत चर्चे दी गई शर्तियों के प्रयोग में अग्रहणित है। उक्त नोटिस में वर्णित तिथि पर जारी नोटिस राशि का वास्तविक कब्जा कब्जा कर दिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से संघर्षित के साथ सीधा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संघर्षित के साथ कोई भी लेन-देन संबंधित तिथि से भावी व्याज की राशि, लागत और शुल्क के साथ यहाँ निर्दिष्ट राशि **एचएडीबी फाइनॅसियल सर्विसेज लिमिटेड** के प्रभार अधीन होगा। ऋणीय/सह-उधारकर्ता/गारंटरी का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, मांग नोटिस की तिथि: रुपये में दावा की गई राशि, प्रतिभूति का विवरण, कबजे की तिथि नीचे दिए गए हैं।

1) ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथि 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कबजे की तिथि

1) **उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नाम:** नीतू सिंह, निवासी मकान नंबर सी-282 संख्या, 100 गैलमसुद नगर नोएडा 20101 प्रदीप कुमार मकान नंबर सी-282 संख्या, 100 गैलमसुद नगर नोएडा 20103; **ऋण खाता संख्या:** 1005597 **ऋण राशि:** र. 10,00,00,000/- (कैश एवं कैशेड रुपये), डिमांड नोटिफ़िकेशन: 04.06.2024, **दावा की गई तिथि:** 26.05.2024 तक र. 37,088,911.38/- (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ ग्यारह और पैसे अठ्ठासी मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संचितकृत व्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का विवरण:** संघर्षित संख्या 47, ब्लॉक जे भुल्ल, सेक्टर 18, नोएडा जिला नोएडा गुरु नानक 201301 में स्थित संघर्षित का समुष्पि टुकड़ा अपन। **संघर्षित क्षेत्र:** 1548 वर्ग फीट – **डीआईए** उत्तर-अन संघर्षित, **डीआईए** रोड, प्लॉट नंबर 46, **परिधान:** प्लॉट नंबर 46, **कबजे की तिथि:** 22.08.2024

2.उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नाम: आरम गार्मैसस एएस/ 3630, गीता गली, गली नंबर-05, धर्मपुरा, गांधी नगर, दिल्ली दिल्ली-110031 दिल्ली और साथ ही संघर्षित संख्या ई-100, खसरा नंबर-750, गांव बांडा, गुजरात खारद जगजीत नगर, साराथि, दिल्ली, दिल्ली-110023, अरुण सिंह मकान नंबर-ई-100, पल्ली मंजिल, ख नंबर-750307 पूना जगजीत नगर, धर्मपुरा गुरुजी बाबाजी, दिल्ली दिल्ली-110043 दिल्ली अरम गार्मैसस एएस/3630, गीता गली, गली नंबर 719 / 52-1/4-1/-1/-1/1 प्लॉट नंबर 14, पल्ली नंबर-20 धर्मपुरा गीता नगर दिल्ली-110031 दिल्ली, रानी आई-100, जी/एफ खान-750, पुस्तान-3, जगजीत नगर दिल्ली पंचार मंत्र 60 प्लॉट रोड दिल्ली दिल्ली-110053, **ऋण खाता संख्या:** 6880984 **ऋण राशि:** र. 26,00,976/- (छब्बिस लाख नौ सौ सत्तर छह रुपये मात्र) **आवेदन तिथि:** 07.06.2024, **दावा की गई तिथि:** 07.06.2024 तक र. 91,840,95/- (नौ लाख चौदह हजार आठ सौ तीन रूप्य और पचास पैसे मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संचितकृत व्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **प्रतिभूति का बर्णन:** गांव-बांडा, गुजरात खारद, जगजीत नगर, साराथि, दिल्ली-110053 में 60 वर्ग गज में से 30 वर्ग गज मात्र पते 25.083 वर्ग मीटर मात्र वाले भूतल तकई परिया, निम्नो मुखई की आखिरी मंजिल तक निम्निके सभी अधिकार के साथ संघर्षित संख्या ई-100, खसरा संख्या 750 में से, वाली सम्पत्ति का वह समुष्पि टुकड़ा और और अन्य की संघर्षित अन्य की संघर्षित मूल सड़क अन्य की संघर्षित **डीआईए** पूर्व- अन्य की संघर्षित, **परिधान:** अन्य की संघर्षित, **उत्तर-अन** गुजरात संरक्ष, **दक्षिण:** अन्य की संघर्षित, **कबजे की तिथि:** 20.08.2024

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संघर्षियों को भुगतान के लिए, उधारकर्ता समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत शर्तियों के प्रयोग में अग्रहणित है। उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरुण यादव कोन, 8908080808 (9914103084) से संपर्क करें।

स्थान: दिल्ली, दिनांक: 24.08.2024 हस्ता /-अधिकृत अधिकारी, एचएडीबी फाइनॅसिजल सर्विसेज लिमिटेड के लिए,

CORDS®
पंजीकृत कार्यालय: 94, धर्म तल, शेषू देवराय चाम मार्ग, ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पास, तीसरा चरण, गुप्ता इन्डियन नगर, नई दिल्ली-110020

खबर कोना



नई दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी ,दोपहिया वाहन लेकर जाता एक व्यक्ति ।

‘जेड प्लस’ सुरक्षा प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है : पवार

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें दी गई ‘जेड प्लस’ सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने पवार को बुधवार को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा प्रदान की। यह अतिविशिष्ट व्यक्ति (वीआईपी) को दी जाने वाली सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा है। राजनेता (83) ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बारे में पूछने पर गुरुवार को नवी मुंबई में पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस कदम के पीछे के मकसद की जानकारी नहीं है। पवार ने कहा, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि सरकार ने तीन लोगों को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक हूँ... अन्य दो लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं।

सरकार ने ई-कामर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने देश में ई-कामर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) स्थापित करने के लिए उद्योग जगत से प्रस्ताव मांगे गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस में कहा, प्रस्ताव के आधार पर निर्बाध तथा शीघ्र निर्यात मंजूरी की सुविधा के लिए ईसीईएच के लिए साफ्टवेयर आवश्यकताओं सहित अन्य विवरण तय किए जाएंगे। इस संबंध में इन केंद्रों के संचालन के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। डीजीएफटी ने कहा, इस संबंध में, ईसीएचओ की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव जांच, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए निदेशालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार ने बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत ई-कामर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी। देश में शुरुआत में 10-15 केंद्र स्थापित करने की योजना है।

‘एमएसएमई, नवउद्यम का बड़ी परियोजनाओं की तरह स्वागत करेंगे’

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राज्य सरकार बड़ी परियोजनाओं के समान ही लघु एवं मझोले उद्यमों तथा स्टार्टअप इकाइयों का ‘लाल कालीन’ बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद राज्य को वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) केंद्र में बदलना है। सामंत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ (एआइएआइ) द्वारा 8-10 अगस्त, 2024 तक डब्ल्यूटीसी मुंबई में आयोजित ‘फिनटेक: डिजिटल क्रांति में तेजी’ विषय पर नौवें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। आयोजकों द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस अवसर पर मंत्री ने कहा, फिनटेक ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में क्रांति ला दी है और इसमें एमएसएमई और नवउद्यम क्षेत्रों को समर्थन देने की क्षमता है। हमारी सरकार मुंबई को वैश्विक फिनटेक केंद्र में बदलने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगी।

फेडरल रिजर्व बैंक के संकेतों से पहले बाजार में रहा उतार-चढ़ाव



मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व बैंक) के चेयरमैन के अहम संबोधन से पहले मिले-जुले वैश्विक रुझानों के बीच शुक्रवार को आइसीआइसीआइ बैंक और भारती एअरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में लिवाली से स्थानीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 33.02 अंक यानी 0.04 फीसद बढ़कर 81,086.21 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त पर रहा। शुक्रआती कारोबार में सूचकांक 169.93 अंक गिरकर 80,883.26 अंक के निचले स्तर पर आ गया था। बाद में यह 178.3 अंक उछलकर 81,231.49 अंक के उच्चस्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अंत में इसने बढ़त गंवा दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 11.65 अंक या 0.05 फीसद बढ़कर 24,823.15 अंक पर बंद हुआ। यह निफ्टी का बढ़त का लगातार सातवां सत्र रहा। सूचकांक की कंपनियों में टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल, भारती एअरटेल, बजाज फिनसर्व, आइसीआइसीआइ बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील लाभ में रही। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, टाइटन, इंफोसिस, भारतीय स्टेट

डालर के मुकाबले रुपया चार पैसे चढ़कर 83.89 पर

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

रुपया शुक्रवार को सीमित दायरे में कारोबार करते हुए डालर के मुकाबले चार पैसे की बढ़त के साथ 83.89 (अस्थायी) पर बंद हुआ। जैक्सन होल संगोष्ठी में फे-डरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण से पहले कारोबारियों के सतर्क रख अपनाने से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कमजोर अमेरिकी डालर, विदेशी पूंजी के प्रवाह और घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख ने रुपए को सहारा दिया। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी ने तेज बढ़त को रोक दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 83.93 पर खुला और दिन में कारोबार के दौरान 83.85 के उच्च स्तर तक गया। रुपया कारोबार के अंत में डालर के मुकाबले 83.89 (अस्थायी) पर बंद हुआ

बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट रही। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के भाषण से पहले भारतीय सूचकांक सपाट स्तर के आसपास झुलते रहे और मिश्रित वैश्विक बाजार धारणा ने इस परिदृश्य को और अधिक तेजी दी। नायर ने कहा कि निवेशक सावधानी बरत रहे हैं और नीतिगत ब्याज दर को लेकर अधिक जानकारी के लिए



जो पिछले बंद स्तर से चार पैसे की बढ़त है। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया तीन पैसे टूटकर 83.93 प्रति डालर पर बंद हुआ था। शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि रुपए के थोड़े नकारात्मक रुझान के साथ कारोबार करने की आशंका है। कारोबारी जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के भाषण से पहले सतर्क बने हुए हैं।

पावेल के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा जबकि यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 1,371.79 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,971.80 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआइ को

कोलकाता, 23 अगस्त (भाषा)।

कलकता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह निर्णय अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद लिया गया है, जिन्होंने कालेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआइ को तीन सप्ताह में जांच से संबंधित प्रगति रपट प्रस्तुत

नई दिल्ली

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674.66 अरब डालर

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त को समाप्त में 4.54 अरब डालर बढ़कर 674.66 अरब डालर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 अरब डालर घटकर 670.11 अरब डालर रहा था।

आरबीआइ की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.60 अरब डालर बढ़कर 591.56 अरब डालर हो गईं। डालर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। समीक्षाधीन

समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 86.5 करोड़ डालर बढ़कर 60.10 अरब डालर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) छह करोड़ डालर बढ़कर 18.34 अरब डालर हो गए।

सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 86.5 करोड़ डालर बढ़कर 60.10 अरब डालर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) छह करोड़ डालर बढ़कर 18.34 अरब डालर हो गए। आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 1.2 करोड़ डालर बढ़कर 4.65 अरब डालर हो गया।

डीजीसीए ने एअर इंडिया पर लगाया 90 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

विमानन नियामक डीजीसीए ने अयोध्या चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए एअर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एअर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः छह लाख रुपए और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित पायलट को आगाह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसमें कहा गया, एअर इंडिया लिमिटेड ने एक ‘नान-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ द्वारा संचालित उड़ान-संचालन किया, जिसे एक ‘नान-लाइन-



रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर ‘शेड्यूलिंग’ घटना पाया है जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।

एअरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वेच्छिक रपट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एअरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी।



रत्नागिरी में पारंपरिक बैल दौड़ कार्यक्रम ‘नांगरानी’ उत्सव के दौरान अपने बैलों के साथ दौड़ता हुआ एक किसान।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीक्षांत समारोहों के लिए परिधान नियम तैयार करने को कहा

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 23 अगस्त ।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी संस्थानों से कहा है कि वे दीक्षांत समारोहों के लिए उस राज्य की परंपराओं के आधार पर एक उपयुक्त भारतीय परिधान नियम तैयार करें जहां वे स्थित हैं। मंत्रालय ने कहा कि काले रंग की पोशाक और टोपी पहनने की वर्तमान प्रथा एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसे बदले जाने की जरूरत है। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा दीक्षांत समारोह के दौरान काले रंग की पोशाक और टोपी का उपयोग किया जा रहा है। उसने कहा

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा दीक्षांत समारोह के दौरान काले रंग की पोशाक और टोपी का उपयोग किया जा रहा है। उसने कहा कि इस पोशाक की उत्पत्ति यूरोप में

कि इस पोशाक की उत्पत्ति यूरोप में मध्य युग में हुई थी और अंग्रेजों ने इसे अपने सभी उपनिवेशों में पेश किया था। पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त परंपरा एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि तदनुसार मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में संलग्न एम्स

मध्य युग में हुई थी और अंग्रेजों ने इसे अपने सभी उपनिवेशों में पेश किया था। पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त परंपरा एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है।

,आईएनआई समेत मंत्रालय के विभिन्न संस्थान अपने संस्थानों के दीक्षांत समारोह के लिए एक उपयुक्त भारतीय परिधान नियम तैयार करेंगे जो उस राज्य की स्थानीय परंपराओं पर आधारित होगा जिसमें संस्थान स्थित है।मंत्रालय ने उनसे इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

रपट

देश के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है

उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों का स्तर सामान्य से कम : सीडब्लूसी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 23 अगस्त।

देश के प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में सामान्य से कम स्तर बना हुआ है। इससे आने वाले दिनों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) की ओर से देशभर के 155 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति पर शुक्रवार को जारी नवीनतम रपट में यह जानकारी दी गई है।

रपट के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण क्षमता 130.800 अरब घन मीटर (बीसीएम) है, जो कुल संग्रहण क्षमता का 72

फीसद है। कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में जल भंडारण स्तर सामान्य से कम है। हालांकि, यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 114.657 बीसीएम से अधिक है।

रपट में जलाशयों के जल-भंडारण स्तरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अन्य की तुलना में बेहतर

(बीसीएम) है, जो कुल संग्रहण क्षमता का 72 फीसद है।

कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के जलाशयों में जल भंडारण स्तर सामान्य से कम है। हालांकि, यह पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 114.657 बीसीएम से अधिक है।

भंडारण स्तर है। उत्तरी क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के जलाशयों में भंडारण स्तर सामान्य से कम है, जहां जलाशयों में उनकी क्षमता का केवल 53 फीसद ही पानी बचा है। यह पिछले वर्ष दर्ज 84 फीसद की तुलना में बड़ी गिरावट है। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों वाले दक्षिणी क्षेत्र में अधिक सकारात्मक रुझान

दिखाई देता है, जहां जलाशयों की क्षमता 80 फीसद है। पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, उनमें भी जल-भंडारण स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में जलाशयों का वर्तमान स्तर 60 फीसद पर है, जो पिछले वर्ष दर्ज 43 फीद की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं, वहां भी जल भंडारण स्तर में वृद्धि देखी गई है। यहां जलाशयों की क्षमता अब 74 फीसद है, जो पिछले वर्ष 69 फीसद थी। मध्य क्षेत्र के इलाके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जलाशयों में वर्तमान में उनकी कुल क्षमता का 76 फीसद जल भरा हुआ है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज 73 फीसद से मामूली सुधार दर्शाता है।

कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सिपाही भर्ती परीक्षा

लखनऊ, 23 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आरक्षी (सिपाही) भर्ती परीक्षा शुक्रवार को राज्यभर के 1,174 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य की राजधानी में कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। परीक्षाएं सुचारू ढंग से हुईं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, परीक्षा राज्य के 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा पांच दिन यानी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जानी है। इसके अनुसार प्रत्येक दिन अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली अपराह्न तीन बजे शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक दिन 9.5 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।

खबर कोना



मास्को : रूस के बाहर नोवो-ओगारियोवो राज्य निवास पर ‘वीडियो कॉफ्रेंस’ के माध्यम से सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।

बांग्लादेश में बाढ़ से 15 लोगों की मौत, लाखों प्रभावित

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

मानसून की भारी बारिश से बांग्लादेश के डेल्टाई इलाकों और भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। इस कारण बांग्लादेश में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जो राजनीतिक परिवर्तन के बाद नगदित अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, खासकर पब्लौर, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में। इस कारण कई शहरों और कस्बों के अलावा सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है और संचार लाइन बाधित हो गई हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बांग्लादेश संवाद संस्था’ (बीएसएस) की खबर के मुताबिक, आपदा प्रबंधन मंत्रालय में सचिव कमर-उल-हसन ने कहा, बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 11 जिलों के 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हसन ने संवाददाताओं को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना, नौसेना, तट रक्षक, बाडर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), अग्निशमन कर्मी, पुलिस और छात्रों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीलंका : राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार का निधन

कोलंबो, 23 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका में अगले महीने की 21 तारीख को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमा रहे 39 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार का निधन हो गया है। उनके परिवार ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर-पश्चिमी पुतुलम जिले के 79 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार इदरीस मोहम्मद इलियास को गुरुवार की रात दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने 1990 के दशक में द्वीपीय देश के उत्तरी जिले जाफना की नौ फीसद मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी का संसद में प्रतिनिधित्व किया था।

फ्रांस के राष्ट्रपति प्रमुख दलों के नेताओं के साथ करेंगे बातचीत

पेरिस, 23 अगस्त (एपी)।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों नई सरकार के गठन के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। पिछले महीने संपन्न हुए संसदीय चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि फ्रांस के मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ शुक्रवार और सोमवार को एलिसी राष्ट्रपति भवन में बैठकें होगी ताकि ‘व्यापक और सबसे स्थिर बहुमत’ की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति इन विचार-विमर्शों और उनके निष्कर्षों के बाद की जाएगी। वामपंथी गठबंधन ‘न्यू पापुलर फ्रंट’ ने पिछले महीने चुनावों में लगभग एक-तिहाई सीट जीती थी जो किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक है। मैक्रों का मध्यमार्गी गठबंधन दूसरे स्थान पर रहा और धुर दक्षिणपंथी ‘नेशनल रैली’ तीसरे स्थान पर रही। आधुनिक फ्रांस के इतिहास में किसी भी प्रभावशाली राजनीतिक दल या गठबंधन का दबदबा न होना, संसद का त्रिशंकु होना और राजनीतिक पंगुता की स्थिति पैदा होने को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में देखा जा रहा है। ‘न्यू पापुलर फ्रंट’ ने जोर देकर कहा है कि सबसे बड़े समूह के रूप में उसके उभरने के बाद प्रधानमंत्री पद पर उसका दावा सबसे मजबूत है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति व डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो देश के लोगों को एकजुट कर सके

शिकागो, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ की उम्मीदवार और देश की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार की वादा किया कि वह ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो देश के लोगों को एकजुट कर सके। हैरिस ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तैयार करने का मौका है। हैरिस (59) अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख दल की उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला हैं।

भारतीय-अफ्रीकी मूल की हैरिस ने शिकागो में गुरुवार रात ‘डेमोक्रेटिक नेशनल कंवेशन’ के दौरान उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद दिए गए भाषण में कहा, इस चुनाव के साथ ही हमारे देश के पास अतीत की कड़वाहट, निराशावाद और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक अनमोल अवसर है। यह किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करने का मौका है।

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आज रात विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले लोग इसे देख रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप यह जान लें कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनने का वादा करती हूं... हैरिस ने कहा, मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो हमें एकजुट करे सके, जिससे हम अपनी बड़ी से बड़ी आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। एक

अमेरिका में ‘हिंदू फार कमला हैरिस’ समूह बनाया

वाशिंगटन, 23 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने

के लिए देश के कुछ हिंदुओं ने मिलकर ‘हिंदू फार कमला हैरिस’ समूह बनाया है। उनका मानना है कि वह भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता होंगी। ‘हिंदू फार कमला हैरिस’ समूह के संस्थापक सदस्यों ने कहा कि ‘कमला देवी हैरिस को अमेरिका की 47वीं राष्ट्रपति’ नियुक्त होने में मदद के वास्ते के यह समूह बनाया गया है।

हैरिस महज एक कठपुतली हैं : विवेक रामास्वामी

शिकागो, 23 अगस्त (भाषा)।

रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उनकी पार्टी में एक मामूली हैसियत है और वह ‘एक कठपुतली हैं।’ रामास्वामी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक

ऐसी राष्ट्रपति जो नेतृत्व भी करे और सभी लोगों की बात भी सुने। जो यथार्थवादी हो, व्यावहारिक हो और जिसमें सामान्य ज्ञान हो



निरीक्षण

नासिक में भारतीय सेना स्कूल आफ आर्टिलरी में हथियारों का अवलोकन करता अमेरिकी सेना का प्रतिनिधिमंडल।

मोदी-योगी की तारीफ करने पर पति ने दिया तलाक अयोध्या के सौंदर्यीकरण की चर्चा पर किया प्रताड़ित

बहराइच, 23 अगस्त (जनसत्ता)।

मुसलिम समुदाय की एक नवविवाहिता द्वारा अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ करने पर उसके पति द्वारा कथित तौर पर तीन तलाक देने और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जरवल रोड के एसएचओ बृजराज प्रसाद ने बताया पीड़िता ने अपनी शिकायत में पांच अगस्त की अयोध्या की घटना बताई है, जिसमें आपसी विवाद के बाद गरम दाल से जलाने व अन्य आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उसी दिन (पांच अगस्त को) अयोध्या की कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन बाद में तीन तलाक व जान से मारने की धमकी की बात सामने आई।

आपबीती

चिंताएं तो हैं, पर बांग्लादेश हमारे दिल के करीब है

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश में 16 साल से अपने परिवार के साथ रह रही एक भारतीय प्रवासी मीरा मेनन का कहना है कि केरल में उनकी मां सुरक्षा चिंताओं के कारण लगातार उनसे देश छोड़ने का आग्रह कर रही हैं, लेकिन उनकी छोटी बेटी को ‘ढाका घर जैसा लगता है’ और इससे अलग होना आसान नहीं है।

जुलाई में बड़े पैमाने पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में भारतीयों ने हिंसाग्रस्त देश को छोड़ दिया है। यह प्रदर्शन शेख हसीना सरकार के खिलाफ एक अभूतपूर्व प्रतिरोध में बदल गया, जिसके कारण उन्हें पांच अगस्त को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। केरल के त्रिशूर जिले की मूल निवासी 45 वर्षीय मेनन अपने पति, (जो यहां एक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करते हैं) और 14 वर्षीय बेटी अवतिका के साथ ढाका में रहती हैं। मेनन ने कहा, हम छुट्टी मनाने के लिए केरल में थे और चार अगस्त को वापस

केरल के त्रिशूर जिले की मूल निवासी 45 वर्षीय मेनन अपने पति, (जो यहां एक कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करते हैं) और 14 वर्षीय बेटी अवतिका के साथ ढाका में रहती हैं। मेनन ने कहा, हम छुट्टी मनाने के लिए केरल में थे और चार अगस्त को वापस ढाका लौटे थे।

ढाका लौटे थे। यह कर्फ्यू वाला दिन था, लेकिन हमें नहीं पता था कि स्थिति एक दिन में इतनी नाटकीय रूप से बदल जाएगी। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वह विरोध प्रदर्शन के दौरान अछूता रहा था। लेकिन रात में सुरक्षाकर्मी गस्त करते हैं और सीटी आदि की आवाज आती है। मेरी नींद भी प्रभावित हुई है। ढाका में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और मेनन (एक गृहिणी) ढाका मलयाली एसोसिएशन (डीएमए) की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, हर साल

देश/दुनिया

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया

ढाका, 23 अगस्त (भाषा)।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है।

अंतरिम सरकार ने यह कदम विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने और भारत चले जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकारों, पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों और हाल में भंग की गई संसद के सभी

यूक्रेन को उपहार के तौर पर चार ‘भीष्म क्यूब’ देगा भारत

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 23 अगस्त।

भारत ने यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से चार ‘भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री (बीएचआइएसएसएम) क्यूब’ सचल अस्पताल उपहार में देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विकासशील देशों को मानवीय सहायता के रूप में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम ‘आरोग्य मैत्री’ के अंतर्गत सरकार ने ‘भीष्म’ पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि यह आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों को आसानी से

नाभा जेल से फरार होने का मामला

हांगकांग से प्रत्यर्पित रोमी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चंडीगढ़, 23 अगस्त (एजेंसी)।

पंजाब में 2016 में नाभा जेल तोड़ने के मुख्य साजिशकर्ता रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को गुरुवार को हांगकांग से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद शक्रवार सुबह पंजाब लाया गया। रमनजीत सिंह को पटियाला जिले के नाभा लाया गया और एक अस्पताल में उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। बाद में उसे अवालत में पेश किया गया जहां से उसे दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, रोमी नाभा जेल तोड़ने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता था जिसमें दो आतंकवादियों समेत छह खूंखार अपराधी भाग गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में 2016 में नाभा जेल तोड़ने के मुख्य साजिशकर्ता

रमनजीत सिंह को गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) और पंजाब पुलिस द्वारा समन्वित एक अभियान में हांगकांग के अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

सीबीआइ के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘सीबीआइ के वैश्विक परिचालन केंद्र ने 22 अगस्त को हांगकांग से भारत में रमनजीत सिंह के प्रत्यर्पण के लिए पंजाब पुलिस और इंटरपोल एनसीबी-हांगकांग के साथ समन्वय किया है।’ उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने पंजाब पुलिस के अनुरोध पर 22 मार्च, 2017 को इंटरपोल महासचिवालय से सिंह के खिलाफ ‘रेड कार्नर नोटिस’ जारी कराया था।

ज्ञातव्य है कि वटिंडा के बंगी रूलटू गांव के निवासी सिंह के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही वर्ष 2018 में शुरू की गई थी।

असम में नाबालिग से बलात्कार, सड़कों पर उतरे हजारों लोग

गुवाहाटी, 23 अगस्त (भाषा)।

असम के नागांव जिले में तीन व्यक्तिों द्वारा एक नाबालिग से कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की घटना के विरोध में राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे धींग इलाके में ट्यूशन से पढ़ाई के बाद साइकिल से घर लौट रही नाबालिग पर तीन लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए और नाबालिग को घेर लिया। उन्होंने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे घायल और बेहोशी की हालत में एक तलाब के पास सड़क के किनारे छोड़ दिया। कक्षा 10 की छात्रा को बाद में स्थानीय लोगों ने

अंतरिम सरकार ने यह कदम विद्यार्थियों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने व भारत चले जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया है।

सदस्यों को मिले राजनयिक पासपोर्ट तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अगस्त में 76 वर्षीय हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद 12वीं संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट भी उनके कार्यकाल या नियुक्ति समाप्त होने पर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे।

उपयोग करने योग्य और तेजी से तैनाती-योग्य साधन प्रदान करता है। यूक्रेन को ऐसे चार क्यूब उपहार स्वरूप देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले लिया गया। यूक्रेन लंबे समय से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। सचल अस्पताल की सभी आवश्यक दवाओं और उपकरणों को घनाकार बक्साें (प्रत्येक 15 इंच) में एक सुव्यवस्थित तरीके से पैक करके बनाया गया है, तथा युद्ध या प्राकृतिक आपदा में होने वाली चोटों और चिकित्सा समस्याओं के प्रकार के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन ‘क्यूब्स’ को एक ऐसे ढांचे पर रखा जाता है जो समायोज्य (अडजस्टबल), मजबूत होता है और वायु, समुद्र, भूमि और ड्रोन द्वारा लाया व ले जाया जा सकता है।

जेल से फरार होकर हांगकांग भागा था

चंडीगढ़ : सोलह अपराधियों ने 27 नवंबर, 2016 को नाभा जेल पर हमला कर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसमें छह वांछित अपराधी भागने में सफल हो गए थेज जिनमें हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर, नीता देओल, गुरप्रीत सेखी, अमन धोतियां और आतंकवादी हरमिंदर मिंटू और कश्मीर सिंह गलवड्डी शामिल थे। जनवरी, 2018 में राजस्थान में पुलिस मुठभेड़ में गौंडर मारा गया, जबकि अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जून, 2016 में हथियार बरामदगी और फर्जी क्रेडिट कार्ड मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगस्त, 2016 में उसे जमानत मिल गई और हांगकांग भाग गया।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब आठ बजे धींग इलाके में ट्यूशन से पढ़ाई के बाद साइकिल से घर लौट रही नाबालिग पर तीन लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया।

देखा और पुलिस को सूचना दी। उसे पहले धींग के एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और बाद में इलाज तथा मेडिकल जांच के लिए नागांव के एक अस्पताल में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, धींग पहुंचे और लिला पुलिस के अधिकारियों के साथ अपराध स्थल का दौरा किया।

ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों, प्रवासी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला

लंदन, 23 अगस्त (भाषा)।

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों, धर्मार्थ संस्थाओं और प्रवासी संगठनों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एंव अस्पताल में कार्यक्रम एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। महिला संगठनों ने लंदन के पॉलियामेंट स्क्वायर और ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में गुरुवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट शांति मार्च आयोजित किया तो वहीं ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया – यूनाइटेड किंगडम’ (एसएफआइ-यूके) ने बुधवार को लिवरपूल शहर में एक मार्च निकालकर इस घटना पर विरोध जताया।



एनआईआईटी लर्निंग सिरस्टन्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं०-85, सेक्टर 32, इस्टीड न्यूक्लियस एरिया, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा
 CMC: 1722004HR2001PLC099478; **फोन:** 0124- 4293000,
वेबसाइट: www.niitlms.com **ईमेल:** investors@niitlms.com

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनआईआईटी लर्निंग सिरस्टन्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को सुबह 10:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन को सूचना में निम्नांकित व्यवसाय के निम्नांकित के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो पद्धति (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनु. प्राधान्यों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रामुखि तथा विनियम बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्ध मान्यएवं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कानून मालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिचय सं. 09/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की धारा 103 के तहत कम्पन के उद्देश्य के लिए दिया जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ बॉर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के पास सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पते डिवाइजिटी प्रमाणिणी(डी) के पास प्रेषित होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.niitlms.com और स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nsdlindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी आम सदस्यों को नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरीस लिमिटेड ("एनएसडीएल") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिपोर्ट ई-वोटिंग) का उपयोग करके रिपोर्टों वोट आने, वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया/विधि, डीमोस्ट्रेशनलाइन्ड मॉड में शेर खरीदने वाले सदस्यों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओवीएम के माध्यम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को डिमोस्ट्रेशनलाइन्ड प्रासम में शेयर धारक करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हक्कदार होंगे। रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे) प्रासम होगी और 23 सितम्बर, 2024 (प्रातः 5:00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट का वोट देने के बाद उचित बदला नहीं जा सकता। यदि रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों मामलों से वोट दिया जाता है तो रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में की गई ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

पी मिलन मलिक, शेयर करकर्ता सचिव (सदस्याता संख्या एफसीसीएन 9888 और सीसीपी संख्या 10614) और उभर अतिरिक्तधि में भी सुभाग प्राप्त दे सेंगिया, चेयरमन सचिव (सदस्याता संख्या एफसीसीएन 30919 और सीसीपी संख्या 23681), कॉन्फ्रेंस संचालक सचिव एनएसडी के नामित प्राधिकारी को ई-वोटिंग एप्लिकेशन की निष्पत्ता और वाररसीटी के तहत से जाब करने के लिए जानकारी के रूप में निशुचित किया गया है।

सदस्यगण को एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीजीई-नेट आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिग्रेडेशन नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर समित करने हुए अनुपालन पर कंपनी के पास investors@niitlms.com पर मेकअप जानकारी कर सकते हैं। एजीकर सडिस्टेशन मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 तक खुला रहेगा। कट-ऑफ तिथि की शेयर धारक करने वाले सदस्यगण पंजीकरण पर एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। जो भी सदस्यगण कोई भी पुष्टताय या जानकारी चाहते हैं, उन्हें अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@niitlms.com पर ईमेल लिखकर भेजें।

ई-वैज पता/ईक विवरण पंजीकरण/अपवोट की प्रक्रिया

डिमोस्ट्रेशनलाइन्ड प्रासम में शेयर धारक करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिवाइजिटी प्रमाणिणी के पास आम ई-मेल पता/ईक विवरण पंजीकरण/अपवोट करें।

समाप्त/घोष पर कर कटौती (टीडीएस)/विडियोडिग्रेडेशन पर जानकारी

निदेशक मंडल ने 22 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 2,75/- , प्रति इक्विटी शेयर औसत लागत की फिक्सीरति है। एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद अगला का भुगतान उस सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम बुकप्रासिंग, 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के बैंकड्राफ्ट या शेयरों के लागूनी स्थानियों के रूप में डिमोस्ट्रेशन के निर्देश में शामिल होंगे। अंतिम लागूनी स्थानियों में सदस्यों की भुगतान की अवधि उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान (घोष पर कर कटौती के बाद) किया जाएगा जिनमें कोई भी वसूली के बाद का विवरण अपवोट किया है। निम्न शेयरधारकों ने वीकैट घोष में अपने बैंक खाते का विवरण अपवोट नहीं किया है उनके पंजीकृत पते पर लागूना राश को डिमोस्ट्रेशन/वैक भेजें अपने पते। लागूना प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लागूना प्राप्त करने के लिए अपने डिमोस्ट्रेशन के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण अपवोट करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्ति अधिनियम, 2020 का अनुच्छेद अद्ययावक अधिनियम, 1981 ("आईटी अधिनियम") में अडिस्टेशन दिना मास है कि 1 अगस्त, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या निशित लागूना शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लागूना का भुगतान करने समय घोष पर कर कटौती (टीडीएस) का ध्यान रखना होगा। हमें ज्ञात, उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में समय बचाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्राधान्यों के अनुसार नीचे निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए, अधिनियम की धारा 194 के तहत घोष पर कर कटौती निम्नानुसार की जाएगी:

वैज संचाली लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक : 10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेख शेयरधारक निशित पास वैन/वैज पैन नहीं है। 20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

हालांकि, रेजीडेंट शेयरधारक शेयरधारकों के देय लागूना पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उचित प्रासम होत जाता कुल लागूना रु. 5,000/- से अधिक नहीं है और वह व्यक्ति है जो नई शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है अथवा पैन 1500/-/वॉन 15000 (वॉन 15000 60 वॉ या अधिक आय के रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लागू) प्रदान करते हैं। रेजीडेंट शेयरधारक कर्म/भूय पर कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 1500/-/15000 या ऊपर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरधारकों के लिए पैन अनिवार्य है।

नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए प्रातः 195 के प्राधान्यों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार भाग्य दूरी पर कर निर्देशक करमा आवश्यक है। देय लागूना राशि पर विडोस्ट्रेशन टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अधिवार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसा होगा। हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों के पास भारत और शेयरधारक(की) का टैक्स रेजिडेंस, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक है, देश के भीत बहुपक्षीय सामन ("एनएसडी") के साथ पड़े जाने वाले दोहरे कर भाग्य सभाजित (डीटीए) के प्राधान्यों द्वारा शासित होने का विषय है। इस उद्देश्य के लिए एनएसडी के साथ पठित डीटीए के तहत लागू भाग्य करने के लिए नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों को डिमोस्ट्रेशन प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा अडिस्ट पैन काई की रन-समाप्ति प्रति.
- डिस्ट देयत का शेयरधारक निवासी है उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स रेजिडेंस प्रमाणपत्र का रन-समाप्ति प्रति.
- भारतीय आयकर नोर्टल पर विधित्त भरे गए फॉर्म 100फ की प्रति। इस फॉर्म को नीचे दिए गए विवरणों के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर प्रात पर साबित करना होगा; <https://portal.incometax.gov.in/iceo/assessments/assess-logoutregister>
- नॉन-रेजीडेंट से रन-घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शामिल करती है:
 - नॉन-रेजीडेंट संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है;
 - लागूना आम प्राप्त करने वाला नॉन-रेजीडेंट रेसी भाग का लाभकारी रमनी है;
 - लागूना आम भारत में किसी भी स्थानीय प्रस्थिधान ("पीई") या निशित आधार से संबंधित/प्राप्ती के से वृद्धी नहीं है।
- नॉन-रेजीडेंट प्रासंगिक कर संधि और एनएसडी के तहत प्राधान्यों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है।
- नॉन-रेजीडेंट के पास भारत में प्राम्नी प्रबंधन का स्थान नहीं है;

निदेशीय जानकारी निम्नोक्त/विदेशी शेयरधारकों निदेशकों के माध्य में आईटी अधिनियम की धारा 106(1) के तहत उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के अंतिम 20 प्रतिशत (साथ ही लागू अधिवार और उपकर) या एनएसडी के साथ पठित प्रासंगिक डीटीए में प्रदान की जा सकती है, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर काटा जाएगा।

यह सूचना परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लर्निंग सिरस्टन्स लिमिटेड द्वारा, /- दीपक बंसल कंपनी सचिव	
स्थान: गुरुग्राम, दिनांक: 23 अगस्त, 2024	



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रैस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु की का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
कॉन्टैक्ट नंबर : श्री लियम कुमार गौतम – मोबाइल नंबर 8287233717



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रैस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरु की का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
कॉन्टैक्ट नंबर : श्री लियम कुमार गौतम – मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना			
क्र. सं.	ख़ाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, संबंदधताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन
1.	ऋण ख़ाता सं. HE01DE00000025240, HE01DE00000026627 1. प्रतीक अरोड़ा (आवेदक) 2. प्रतीक अरोड़ा (आवेदक) 3. दिनेश जी (सह-आवेदक) 4. शक्ति कुमार अरोड़ा (सह-आवेदक) सभी निवासी: मकान नंबर 804, प्रथम तल, ऋषि नगर, शकुनवली नदी बाग, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034 प्रथम तल, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजे-344-ए, प्लॉट नंबर 3, ग्राम सलीमुपुर, ऋषि नगर, शारदा, दिल्ली-110034	07-05-2024 21.29,382/-	प्रथम तल, छत के अधिकांश नहीं, सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजे-344-ए, प्लॉट नंबर 3, परिपाम 93 वर्ग फुट (77.748 वर्ग मीटर) ख़रारा नंबर 370, रोड नंबर 44, ग्राम सलीमुपुर, माजरा मादीपुर, दिल्ली, कोलानी अर ऋषि नगर, नारी बाग, के नाम से ज्ञात, दिल्ली-110034, कोमरा पाकिंग, उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के यथानुगत प्रहोहबंद अधिकाधिक सहित। चौहद्दी निम्नानुसार : पूर्व : गली 12 फीट, पश्चिम : उक्त सम्पत्ति का बाकी हिस्सा, उत्तर : अन्य सम्पत्ति,
2	ऋण ख़ाता सं. X0HEED00001660983 1. आशा नारी (आवेदक) 2. रमेश कुमार अरोड़ा (सह-आवेदक) नारी निवासी – 19 जी/एफ, एमआईडी, पीता मंडी, पश्चिम विहार, नंदी दिल्ली-110087	05-10-2020 94,02,645.61/-	डीडीए पलेट नंबर 19, भू तल, कैंट – एसएफएस –1], स्थित मागिल लेक अपार्टमेंस, पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087
			क़ाता का प्रकार
			सांकेतिक

1 ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया <https://chola-lap.procure247.com/> एवं <https://cholamandalam.com/auction-notices> देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस दी है

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 24-08-2024



एसएमएफजी इंडिया होम फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(पूर्व मैंगलूरन इंडिया होम फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
 कॉर्पोरेट कार्यालय: 550 और 504, 4वीं मंजिल, ईशान्यविकी, बीकेसीमैगनस, बांद्रा मुंबई कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051
 पंजी. कार्यालय: सेक्टर 32, इस्टीड न्यूक्लियस, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना (पारिशिट IV) नियम 8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में मुंबुदूरन इंडिया होम फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में एक हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वाधिन्य वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) विविध परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण द्वारा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(2) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित सभी और उस पर व्याज की प्रतिय की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उस के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर व्याज के लिए 'एसएमएफजी' के मुक्त के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर (ओं)का नाम लेन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कबजे की तिथि
1.	लैन – 61153911040838 1. रमन जी 2. सरोज रानी	मकान नं. 1366 (पुराना मकान नं. 1523) नगरपालिका स्थायी संपत्ति आईडी नं. 97C118U17 माता 84 वर्ग गज, विमान मारतुपुर हवेली माहिला (पुलर का पुराना महेला) जगधारी तहसील जामोरा, जिला यमुना नगर	11.05.2024 रु. 16,22,973/- / (09.05.2024 तक रुपये सोलह लाख बाईस हजार नी चौ सित्तर मात्र)	22.08.2024.

स्थान : यमुना नगर, दिल्ली

दिनांक: 22.08.2024



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
बरेली शाखा 118-ए, सचिवल लाइन्स, बरेली-243001

क्र. सं.	ऋणी / बंधककर्ता व गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री आरजे नवी पुत्र श्री अम्वुल करीम निवासी- 23, सेमल खेड़ा, अमर उजाला प्रेस के पास, बरेली (ऋणकर्ता), श्री अम्वुल करीम पुत्र श्री इतवारी, निवासी-23, सेमल खेड़ा, अमर उजाला प्रेस के पास, बरेली	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पारसल स्थित मोहरला सेमल खेड़ा, पुराना शहर, नहरसी और जिला बरेली, क्षेत्रफल 80.34 वर्ग मीटर	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रु. 10,12,544.98	22.08.2024	9,03,21,615.7 + अगामी व्याज + अन्य शुल्क
2.	श्री अम्वुल करीम के नाम (गारंटर एवं बंधककर्ता) और श्री अरुण शीमाबाई-पूई-4 फीट चौड़ा सड़क, पश्चिम संस्कार का मान्य, उत्तर सेमल खेड़ा, निकट अमर उजाला प्रेस, बरेली (गारंटर)	श्री अम्वुल करीम के नाम, शीमाबाई-पूई-4 फीट चौड़ा सड़क, पश्चिम संस्कार का मान्य, उत्तर सेमल खेड़ा, निकट अमर उजाला प्रेस, बरेली (गारंटर)	दिनांक 06.11.2023 तक + अगामी व्याज + अन्य शुल्क	22.08.2024	रु. 9,03,21,615.7 + अगामी व्याज + अन्य शुल्क



एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: सुविट नं. 103, प्रथम तल, सीईडब्लू स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ली रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400055
शाखा का पता: शां पं. 13, तीसरा तल, यमुना नगर कॉम्प्लेक्स, मुक्तिजगह रोड, विदर्भ हॉस्पिटल के निकट, विन्हा नगर, अकोला-444004

नीलामी गृह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
जैसा कि वित्तीय परिसमर्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षर ने यहां नीचे वर्णित प्रतिभूति परिसमर्तियों का कब्जा कर लिया है तथा सम्पत्ति का मौखिक कब्जा करते समय "स्क्रेप सामग्री" भी रिक्वर की गई। अब, इस सूचना सह प्रकाशन द्वारा हम ऋणधारक/सह-ऋणधारक/माटीजगह/गारंटर तथा आम जनता को सूचित कर रहे हैं कि इस प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर इन सामग्रीयों का दावा करें इन चल सामग्रीयों का निपटारा करने के लिये प्रस्ताव/वित्तीय आर्मात्रित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा "जैसा है जहां है आधार", "जो भी जैसा है आधार", तथा "जो कुछ भी वहां है आधार" पर प्रतिभूति क्रेडिटर के कब्जे में नीचे वर्णित संपत्ति में ऋण राशि के लिये इन सामग्रीयों की बिक्री से वसूल की गई राशि को समायोजित करेंगे। विवरण नीचे दिये गये हैं:

ऋणधारक/सह-ऋणधारक का पता	अचल सम्पत्ति का विवरण/ कबजे की तिथि
1. मै. थापा पॉल्टी फार्म,	स्क्रेप सामग्री
2. श्री नर बहादुर थापा	
3. श्रीमती सीता थापा	
सभी निवासी: सेवली, प्रेमनगर, बड़ोवाला, आर्केडिया ग्रान्, परगणा सेन्ट्रलदून, देहरादून-248007,	
राशि रु. खतौनी खताना नं. 6209 / (1399 से 1404 फरसती), खसरा नं. 1800/2 का भाग। आर्केडिया ग्रान्, परगणा सेन्ट्रलदून, देहरादून-248007	

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसमर्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के प्रति आश्चर्य को बताते हैं।

हस्ता: देरानुग

तिथि: 23 अगस्त, 2024



मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: टीसी नंबर 14, 207-7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम- 695034
सीईओप नं. –U69252K1L2010PLC025624,
कॉर्पोरेट कार्यालय: 12थ 01, 14वीं मंजिल, विली क्रैसंजो , प्लॉट नंबर-सी 38 –सी 38, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुम्बई-400051, फ़ोन नं. 0 22-62728517, ई-मेल : contact@cmuthoot.com

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)], कब्जा-सूचना(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंस्थितियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत मेसर्स मुथूट हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और उन्होंने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को एक नाम नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की प्रतिय की तारीख से 60 दिन पूर्व जारी किया गया था कि अधोहस्ताक्षर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने के बाद, ऋणीक/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	लैन/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया वसूली (रु.) बस्यथा में लागू व्याज	कब्जा- तिथि
1	लैन नं. 13100079906 1.रंजणी सिंह छद्द, सिंह शेखावत, 2. कंचन कंजर	20-मई-2024	13-मई-2024 तक रु.8,21,478.71 /-	22-अगस्त-2024

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण: स्क्रीम कॉलोनी, मोती नगर, व्हीस रोड, अजमेर रोड पर, जयपुर खातीपुरा, के नं. 222, मानग, गुरुनिगास सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान – 302021 क्षेत्रफल 88.22 वर्ग गज वाली संपत्ति प्लॉट नंबर 56-ए, का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश । सीमा: पूर्व- पल्लि नंबर 56-बी पश्चिम- पल्लि नंबर – 55 उत्तर- पल्लि नंबर – 56 दक्षिण- 30 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क

2 लैन नं. 13270099863
1. रतन गोविंद राम राजन, 2. गोविंद राम

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण: संकल्प संख्या 1(56) गांव कोलाना तहसील लाडपुरा, जिला – कोटा, राजस्थान – 324001 में क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट वाली संपत्ति मकान पहा सं. 70 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश जो पर है। इसकी सीमा: पूर्व- उत्तरी की भूमि और सड़क ,पश्चिम- स्वयं का बाड़ा, उत्तर- स्वयं का बाड़ा, दक्षिण: लालायरा का मकान,

3 लैन नं. MHFLPURJP1000005001573
1. पवन गोड़, 2. रंजना गोड़

प्रतिभूति संपत्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण: आवासीय भूखंड संख्या 44-ए, स्क्रीम मधुवन कॉलोनी, गांव जामडोली, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान – 302031 वाली संपत्ति वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, पूर्व-पश्चिम 33 फीट और उत्तर-दक्षिण 16 फीट 6 इंच कुल क्षेत्रफल 60.50 वर्ग गज निर्माण 595 वर्ग फीट आरसीसी निर्मित है, संपत्ति श्रीमती रंजना गौर के नाम पर है। सीमा: पूर्व:- भूखंड संख्या –44-बी पश्चिम- 30 फीट सरकारी सड़क उत्तर: भूखंड संख्या 44 दक्षिण: भूखंड संख्या 44

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरिक्त निर्दिष्ट मांग-राशि और अन्य मास्य मेसर्स मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
2024 के सी.ए. (सी.ए.ए.) संख्या 6/सीएनडी/एचआरवाई के मामले में:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और 234 तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और सामागेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्राक्कानों के तहत याचिका
और
निम्नलिखित के बीच सम्मेलन की योजना के मामले में:

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो 18 मई, 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई थी और भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसका अस्तित्व जारी रखा गया है, जिसका सीआईएन : U67100HR1998PTC113312 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइटम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 में है।

...आवेदक कंपनी/हस्तांतरित कंपनी के साथ
पाइन लैब्स लिमिटेड , सिंगापुर् यूईएन नंबर 201319166R, के साथ शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी है, जो सिंगापुर् के कंपनी अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय 38, बीच रोच, नं॰ 29–11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर्, 189767 में है।
...गैर-आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी और
उनके संबंधित शेयर धारक

फॉर्म नं. सी.ए.ए. 2
आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 12 अगस्त, 2024 के आदेश ("आदेश") द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("न्यायाधिकरण") की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी" के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों के बीच विचार करने के उद्देश्य से तथा यदि उचित समझा जाए तो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी और पाइन लैब्स लिमिटेड, अर्थात् गैर-आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") की धारा 230–232 के साथ पठित धारा 234 और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और सामागेलन) नियम, 2016, और सिंगापुर् के कंपनी अधिनियम 1967 की धारा 212 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सहित धारा 210 के अनुरक्षण में ("**योजना**") संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अनुमोदन देने के लिए अलग-अलग वर्युअत बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के पालन में और उसमें दिए गए निर्देशानुसार, आगे की सूचना ("**सूचना**" या "**सूचनाएं**") दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2023 को हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग वर्युअत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("**वीसी**") ("**बैठकें**") के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, (बैठक के लिए मानद स्थान पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइटम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 है) इस प्रकार, आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और / या अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस समय बैठक में भाग लें, विचार करें, और यदि उपयुक्त हों, तो अधिनियम की धारा 232 (1) के साथ पठित धारा 230 (1) के तहत निर्धारित अपेक्षित बहुमत से योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पारित करें :

क्र. स.	बैठकें	दिन और दिनांक	समय
1	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 11 बजे
2	अप्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 12 बजे

रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प चुनने वाले इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदारों को केवल बैठकों में शामिल होने और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन बैठकों के दौरान फिर से वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग लेने और वोट करने के अधिकार रखने वाले व्यक्ति, वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली उक्त बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से वोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2023 तक शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार हैं, उन्हें केवल ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का अधिकार होगा। आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी ने आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को वीसी के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, भाग लेने और ई-वोट करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**केफिन**") को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय पर शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिन द्वारा वोटिंग के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार वोटिंग के लिए केवल एक मूठ चुन सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग।

योजना की प्रतियां, बैठकों के लिए नोटिस और अधिनियम की धारा 230 (3) के तहत व्याख्यात्मक वक्तव्य और इसमें संश्लिप्त सभी दस्तावेज केफिन की वेबसाइट (<https://emeetings.kfintech.com>), और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी की वेबसाइट (www.pinelabs.com) पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट संख्या 408, चौथी मंजिल, टाइटम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 और कंपनी के नेगम कार्यालय कैंडोर टेकस्पेस, चौथी और पांचवीं मंजिल, टॉवर-6, प्लॉट संख्या बी-2, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, भारत में शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच बैठकों की तारीख तक और बैठकों में भी नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखने के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है।

बैठकों के लिए नोटिस की प्रतियां संलग्न दस्तावेजों के साथ, 23 अगस्त, 2024 को आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को 31 दिसंबर, 2023 तक, उनके अंतिम ज्ञात ई-मेल पता पर, जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास उपलब्ध हैं, अनुमत तरीकों (अर्थात् ईमेल) द्वारा भेजी गई हैं। बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के संबंध में निर्देशों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा उक्त नोटिस का संदर्भ देखा जा सकता है।

यदि कोई ऐसा इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, जिसका ई-मेल पता आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, और वह नोटिस की सौंपत कंपनी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्राप्त करना चाहता है तो उनसे अनुरोध है कि वे cosecy@pinelabs.com, पर ई-मेल भेजें, साथ ही उन इक्विटी शेयरधारक(कों) या अप्रतिभूत लेनदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रदान करें, जिसमें बैठक की सूचना और बैठक की तिथि तक ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और स्व-सत्यापित पैन प्रति (और मौखिक फोनियों के मामले में इक्विटी शेयरधारक होने पर शेयर प्रमाण पत्र की एक प्रति) प्रदान करें, और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इन इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को नोटिस की सौंपत कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्रदान की जाएगी।

यदि कोई इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दस्तावेजों को मौखिक रूप से देखना चाहता है तो संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार को मांग प्राप्त होने के एक दिन के अंदर नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखकर एक ईमेल भेजा जा सकता है।

ये बैठकें वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदार की मौखिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, बैठकों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जबकि एक निकास कॉर्पोरेट जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरित कंपनी का इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, उसे वीसी के माध्यम से आयोजित बैठकों के दौरान भाग लेने और/या मतदान करने के प्रयोजनों के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण द्वारा कथित बैठकों के लिए नै-न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.पी. नागरथ को अध्यक्ष तथा श्री विवेकजीत सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

न्यायाधिकरण ने सुश्री अश्वंदीप कौर जज, कंपनी सचिव को उक्त बैठकों का सवैक्षक नियुक्त किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी सहायता या सिकायत के मामले में संबंधित शेयरधारक और/या अप्रतिभूत ऋणदाता केफिन के उप महाप्रबंधक श्री एस.बी. राजू से शिकायत कर सकते हैं, जिसका कार्यालय सेलेनियम, प्लॉट 31 और 32, गाछी बावली वित्तीय जिला, नानकमुखा, हैदराबाद–500 032 पर है, einward.ris@kfintech.com तथा evolving@kfintech.com पर केफिन के टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें। यदि यह योजना बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक: 24 अगस्त, 2024	
स्थान: गुरुग्राम	हस्ताक्षर
	इंद्रेश कुमार गुप्ता
	निदेशक, पाइन लैब्स प्रा. लि.
फोन : 0124-6949200;	सीआईएन : 07488823
ई मेल : cosecy@pinelabs.com; वेबसाइट : www.pinelabs.com	

 					
 शाखा के पते में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक सूचना					
 यह आम जनता और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट) के ग्राहकों को सूचित करने के लिए है कि निम्नलिखित शाखा का पता बदल दिया जाएगा। शाखा में वर्तमान में रखे गए सभी खाते / लेनदेन वही रहेंगे। स्थान के पुराने बराम नए पता का विवरण और परिवर्तन की प्रमावी तिथि अनुलग्नक-ए के रूप में नोटिस के साथ संलग्न है। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने लेन-देन के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें/एए स्थान पर जाएं।					
अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें या निम्नलिखित शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। शाखा प्रबंधक का संपर्क नंबर इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक-ए में दिया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट)।					
"अनुलग्नक-ए"					

शाखा कोड	शाखा का नाम	राज्य	पता बदलने की प्रामावी तिथि	पुराने पते (फिनकेयर यूनिट)	नया शाखा कोड	एयू शाखा – स्थान	राज्य	एयू शाखा का पता	एयू शाखा प्रबंधक संपर्क नंबर
10946	भरिंडा	पंजाब	23-09-24	यूआईडी संख्या: MCB-Z3-01037-000, जिला पश्चिम के सामने, हुनग्राज चौक के पास, चौथी रोड, भरिंडा, पंजाब-151001	2398	गुजराबी मार्ग भद्रिका	पंजाब	एनबीबी303/00908, गार्ड फ्लेड, नैने पेलेट पुर के विद्युत ऑफिस – भरिंडा चौकी रोड (हनुमान जी के पुरोहार शिबारा के भीतर), भरिंडा, पंजाब-151001	8288051871

NIIT	एनआईआईटी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं॰ 86, सेक्टर 32, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001, हरियाणा	
CIN: L74899HR1998PLC017233	
फोन: +91 (124) 4293000; वेबसाइट: www.niit.com; ईमेल: investors@niit.com	
41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	

एनआईआईटी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन ऑडियो विडियो पद्धति (ओपीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ("सेबी") (एजीएम बायट्राएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिचय से, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिचय से, सेबी/एस्को/सीएनडी/सीएफडी-बीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिचय" के रूप में संदर्भित) के अनुसारपन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की धारा 103 के तहत कोर्य के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

परिचयों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं संश्लिप्त वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन अपेक्षित दस्तावेजों के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पते निर्धारित प्रतियोगी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.niit.com और ई-वोटिंग अर्थात् वीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल फिक्सीटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके रिमोटी वोट डालने, वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया/निर्देश, डीपॉजिटरीआइडन मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिनसे अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंगशामिल होंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.nsiid.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण जिन्हें ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतियोगी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन आईडी/पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इन्स्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को या तो मौखिक प्रास्य या डिपेंडेंसियाइडन प्रास्य में शेयर धारक करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओपीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में भाग देने के लिए एकतरफ होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे) अंतत होगी और 23 सितंबर, 2024 (साम 5:00 बजे) समाप्त होगी। उनके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम पर एक वोट देने की आवश्यकता हो तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य रहेगा और एजीएम में वोट नहीं देई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

की निम्नांकित विध, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएन 2668; सीपी 2388) या उनकी मंजूरी, पेशेवर में भी मोहोरित करना, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएन 11292; सीपी 16686), संश्लिप्त निम्नांकित विह एवं कंपनी को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए सक्षमता के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं, या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिपेंड खाता नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर बर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर भेजकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। स्वीकर पंजीकरण मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 तक खुला रहेगा। कट-ऑफ तिथि को शेयर धारक करने वाले सदस्यगण पंजीकरण एवं एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। जो भी सदस्यगण कोई भी पूछताछ या जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@niit.com पर ईमेल लिखकर संपर्क करें।

केआईटी/ई-नेत पता/बैंक विवरण पंजीकरण/आवेद करने की प्रक्रिया

मौखिक प्रास्य में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपने मास्टर परिचय बोर्ड (एस्को)/एनआईआईएलडी/बीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/70 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023, संलग्न-समय पर श्वाभावशायित के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक, केआईटी विवरण (अर्थात्, पिन कोड के साथ धारा 9, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण इत्यादि) और प्रतियोगियों के धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 अक्टू, 2024 के माध्यम से सभी भी भुगतान करके मौखिक शेयरधारकों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा। ये मौखिक शेयरधारक निम्नांक केआईटी आईएल/कंपनी रिस्कॉर्ड में अंकित नहीं हैं, उनके लाम्बा का भुगतान फिजिकल क्रेडिटों में केआईटी अक्टूड होने पर ही किया जाएगा।

जिन सदस्यों के पास डीमैट प्रास्य में शेयर हैं उन्हें लाम्बा के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए अपने बैंक विवरण ई-मेल पता, डाक पता, संपर्क नंबर और नामांकन विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टीडिपेंडेंट के पास अपने डीमैट खाते में अपडेट करना चाहिए।

इसके अलावा, सेबी ने आदेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैट प्रास्य में ही स्थापनास्थित किया जा सकता है। डीमैटरेडियाइडनेशन के विनियम लाम्बा का पालन करने के लिए सदस्यों को खाता देाी जाती है कि वे पोटेंशियलियों प्रबंधन और लाम्बा भुगतान में आसानी के लिए अपने पास मौजूद शेयरों को मौखिक रूप में डीमैटरेडियाइड करें।

सदस्य आईटी/या कंपनी की वेबसाइट पर अपेक्षित फॉर्म/दस्तावेजों भरने के लिए सेबी मास्टर सॉलर, प्रासंगिक विवरण सके अनुरोध फॉर्म, केआईटी फॉर्म और संपर्क विवरण देस सकते हैं।

लाम्बा/घोत पर कर कटौती (टीडीएस)/विद्योडिन टैक्स पर जानकारी

निदेशक नंबर नं 24 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 0.75/- प्रति इक्विटी शेयर अतिर लाम्बा की सिकारिश की है। एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद लाम्बा का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम इस्तेमालीय 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर एवं शेरों के लाम्बार्थी स्वामियों के नाम में डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शामिल होंगे। अतिर लाम्बा एडमिन में सदस्यों की मंजूरी के अधीन उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान (घोत पर कर कटौती के बाद) किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाता का विवरण अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पत्र लाम्बा वारंट/रिमांड डाट/रक मेजे जायेंगे। लाम्बा प्राप्त करने में देरी से बनने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सेबी खाते में लाम्बा प्राप्त करने के लिए कोलोन नंबर के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, स्व-सत्यापित पर कर और पेन की प्रक्रि के साथ अपने डिपॉजिटरी (यहां शेयर वारंट/रिमांड मोड में रखे जाते हैं) के साथ अपने संपर्क बैंक विवरण अपडेट करें और कंपनी के रजिस्टर एवं ट्रान्झैफर एंज – अकंफिअसाइनमेंटस लिमिटेड (यहां शेयर मौखिक रूप में रखे जाते हैं) के साथ अपडेट करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में अधिविधि 2(15) के तहत, 1 अक्टू, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाम्बा शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। संश्लिप्त कंपनी को अतिर लाम्बा का भुगतान करते समय घोत पर कटौती (टीडीएस) शर्तों की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस पर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्राधान्यों के अनुसार नौने निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए, अधिनियम की धारा 194 के तहत घोत पर कर कटौती निम्नांसार की जाएगी:

वैय स्थायी लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक	10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
रेसे शेयरधारक जिनके पास पैय/वैय पैय नहीं है।	20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

हालांकि, रेजीडेंट शेयरधारक शेयरधारकों को देय लाम्बा पर कोई कर नहीं कटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें प्राप् होने वाला कुल लाम्बा रु. 5,00,00/- से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में भी जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में विधिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15(1)/फॉर्म 15(5) (फॉर्म 15(5) 60 वर्ष या अधिक आय के रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए लागू है) प्रदान करते हैं। रेजीडेंट शेयरधारक रूप/यून कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरधारकों के लिए एन अतिवाद है।

नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए धारा 195 के प्राधान्यों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर कर विदेष्टर कटान आवश्यक है। यह लाम्बा राशि पर विदेष्टरिड टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अतिभार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों के साथ भारत और शेयरधारक(कों) का टैक्स रेजीडेंट, यदि वे उनके लिए लाभदायक हैं, देस के ब्यावहृतीय सामन (एनएसडीएल) के साथ पठे जाने वाले दोहरे कर बचाव समझौते ('टीडीए') के प्राधान्यों द्वारा शासित होने का विवला है। इस उद्देश्य के लिए एनएसडीएल के साथ पठित डीटीए के तहत लागू प्राप्त करने के लिए नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति;
- जिस देस का शेयरधारक भारतीय है उस देस के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स रेजीडेंसी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति;
- भारतीय आयकर पत्र पर विधित्त वर्ष एए फॉर्म 10एफ की प्रति। इस फॉर्म को नौने दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर पोर्टल पर दाखिल करना होगा; <https://portal.incometax.gov.in/efilingervices/efile-login/register>
- नॉन-रेजीडेंट से स्व-घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शामिल करती है:
 - नॉन-रेजीडेंट संबंधित कर सॉफ्ट के ताला का दावा करने के लिए पात्र है;
 - लाम्बां प्राप्त प्राप्त करने वाला नॉन-रेजीडेंट ऐसी आय का निष्कासक स्थानी है;
- लाम्बां प्राप्त प्राप्त करने में किसी भी स्थायी प्रत्येक्षण (पीई) या लिमिटेड आय से संबंधित/प्रमावी रूप से जुड़ी नहीं है;
- नॉन-रेजीडेंट प्रासंगिक कर सॉफ और एनएसडीएल के तहत प्राधान्यों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है;
- नॉन-रेजीडेंट के पास भारत में प्रमावी प्रबंधन का स्थान नहीं है;

विदेशी शेयरधारक निदेशकों/विदेशी पोटेंशियलों निदेशकों के माध्ते में आईटी अधिनियम की धारा 196(1) के तहत उपरवर्त दस्तावेजों को जमा करने के अधीन 20 प्रतिशत (साथ ही लागू अतिभार और उपकर) या एनएसडीएल के साथ पठित प्रासंगिक डीटीएए में प्रदान की गई दर, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर कटा जाएगा।

यह सूचना परिचयों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लिमिटेड हस्ता/— यदि वित्त विसाय मन्त्रीज कंपनी निदेशक
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 23 अगस्त, 2024

 इण्डियन ओवरसीज बैंक	क्षेत्रीय कार्यालय: वीएसएनएस कार्यालय के पास, तेजपल्ली चौखंड, मेरठ –250005
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))	

प्रतिनिधि हित (एवंतर्न) नियम 2023 के साथ पठते हुए अनुबंध 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तितों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सम्बंधित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को बंधक के नाम के सामने दर्शायें गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / अन्य नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर सविधा दर और ब्याज, वस्तुी आदि पर ब्याज संचित अतः करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में अक्षम रहने पर ऋणी/ ऋणियों और उन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को अतः निम्नां के साथ पठते हुए अतः अधिनियम का धारा 13(4) के अंतर्गत एवं प्रदत्त शर्तितों का प्रयोग करते हुए नौने दी गई समस्त/ सम्मतितों का अंतःकरण 22.08.2024 को से लिया है। ऋणी/

